Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-17, अंक-01 01-15 जनवरी, 2022 (पाक्षिक) ₹20

'उत्तराखंड में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है'

दिव्य काशी, भव्य काशी

जन विश्वास यात्रा, उत्तर प्रदेश | विजय संकल्प यात्रा, उत्तराखंड | मोदी सरकार के सुशासन से बदल रही पूर्वोत्तर की तस्वीर

पणजी (गोवा) में भाजपा गोवा सरकार के 10 साल पर रिपोर्ट कार्ड जारी करते व संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में हनुमान गढ़ी मंदिर व सरयू घाट पर भाजपा मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों के साथ पूजा-अर्चना करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

काशी (उत्तर प्रदेश) में मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

काशी (उत्तर प्रदेश) में मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक का एक दृश्य

पुणे (महाराष्ट्र) में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

झांसी (उत्तर प्रदेश) में 'जन विश्वास यात्रा' के शुभारंभ अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **'श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर' का लोकार्पण भारत को एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाएगा: नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 दिसंबर, 2021 को वाराणसी में 'दिव्य काशी, भव्य काशी' कार्यक्रम के तहत 'श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर' का...

09 **'जनता ने उप्र में कमल खिलाने का मन पहले ही बना लिया है'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 दिसंबर, 2021 को अंबेडकर...

12 **'उत्तराखंड में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 दिसंबर, 2021 को हरिद्वार (उत्तराखंड) के...

13 **'विकास के प्रति समर्पित योगी सरकार के गठन का मार्ग पुन: प्रशस्त करें'**

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 17 दिसंबर, 2021 को...

14 **'हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं, वे दंगातंत्र के पुजारी हैं'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 दिसंबर, 2021 को मेरठ में लगभग 23 हजार बूथ अध्यक्षों के...

वैचारिकी

सिद्धांत और नीतियां / **पं. दीनदयाल उपाध्याय**

श्रद्धांजलि

भगवत शरण माथुर नहीं रहे 21

उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरबंस कपूर का निधन 21

लेख

मोदी सरकार के सुशासन से बदल रही पूर्वोत्तर की तस्वीर / **राजू बिष्ट** 26

प्रधानमंत्री मोदी को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भारत के लिए गौरव का पल / **राम प्रसाद त्रिपाठी** 28

मोदी के नेतृत्व में भारत पुराने दोस्त को खोए बिना नए दोस्त बना रहा है / **विकास आनंद** 30

डिजिटल इंडिया लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला रहा है / **राजीव कुमार** 31

अन्य

अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में 29 प्रतिशत की भारी वृद्धि 16

सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के व्यापक कार्यक्रम को मिली मंजूरी 17

हमारा शहर स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए: नरेन्द्र मोदी 22

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, 8 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री अयोध्या 'आरती' में शामिल हुए 23

यूपी + योगी बहुत है उपयोगी 24

'प्राकृतिक खेती से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा, वो हैं देश के 80 प्रतिशत किसान' 25

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

संपत्ति के अधिकार को लेकर जो असमानताएं थीं, उन्हें हमारी सरकार की योजनाएं कैसे दूर कर रही हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है– प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत ही पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। यही तो होता है सशक्तिकरण, यही तो होता है विकास!

जगत प्रकाश नड्डा

उत्तर प्रदेश में आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी के मार्गदर्शन और योगीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जन-जन का विश्वास हासिल किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यूपी की जनता भाजपा को पुनः अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी।

अमित शाह

पहले की सरकारें जनता के हित की जगह अपने वोट-बैंक को ध्यान में रखकर फैसले लेती थीं। मोदीजी ने लोगों को अच्छे लगें ऐसे नहीं, बल्कि जो उनके लिए अच्छे हों ऐसे फैसले लिए...ये वही कर सकता है जिसके मन में सुशासन हेतु दृढ़ विश्वास हो, सुशासन के परिणामों की सुनिश्चितता हो।

राजनाथ सिंह

उत्तर प्रदेश की जनता में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी के प्रति अद्भुत भरोसा और विश्वास है। यूपी में फिर बन रही, भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है।

बी.एल. संतोष

भाजपा नेतृत्व वाले कर्नाटक राज्य में प्रदेश पुलिस ने एसआई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें सभी के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया। समावेशी विकास की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सामान्यतः कई लोग तर्क देते हैं कि भाजपा प्रतिगामी है, लेकिन अब वे सभी खामोश हैं।

नितिन गडकरी

उत्तर प्रदेश राज्य में 79.54 किमी लंबाई के NH-29E के सोनौली-गोरखपुर खंड के 4-लेनिंग को HAM के तहत 2555.50 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया है।

सभ्यता और संस्कृति के केंद्रों की पुनर्प्रतिष्ठा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर' के उद्घाटन के साथ ही देश की सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्रों के गौरव एवं भव्यता को पुनर्प्रतिष्ठित करने का कार्य और अधिक सुदृढ़ हुआ है। देशभर में लोगों ने 'भव्य काशी, दिव्य काशी' कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों की संख्या में इस गौरवशाली समारोह में भागीदारी की। हाल ही में श्री केदारनाथ धाम जो कुछ वर्ष पूर्व बाढ़ से प्रभावित हो गया था, उसका पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इन्हीं प्रयासों के क्रम में करतारपुर गलियारा जिसका हाल ही में निर्माण हुआ था तथा कोविड-19 महामारी के कारण बंद करना पड़ा था, अब पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इसमें कोई संशय नहीं कि सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र देश के लिए शक्ति के वे केंद्र हैं जिनसे राष्ट्र अपनी अनवरत यात्रा के लिए ऊर्जा एवं गति प्राप्त करता है।

अब तक उपेक्षित रहे सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र हाल के वर्षों में देश के लिए प्रेरणा एवं ऊर्जा के स्रोत बनकर उभरे हैं

अब तक उपेक्षित रहे सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र हाल के वर्षों में देश के लिए प्रेरणा एवं ऊर्जा के स्रोत बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के साथ ही यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस पहल को 177 देशों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ जो इसके सह-प्रस्तावक बन गए। जहां योग पूरी मानवता के लिए एक वरदान बन गया है, वहीं कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान पूरे विश्व में इसे स्वीकारा गया है। विदेशों में राष्ट्राध्यक्षों को 'भगवद्गीता' का उपहार एवं उन्हें देश में 'मंदिर-दर्शन' एवं 'गंगा आरती' में आमंत्रित कर भारत के गौरवशाली आध्यात्मिक परंपराओं से विश्व को साक्षात्कार कराने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। 'वसुधैव कुटुंबकम्' के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल-बांग्लादेश सहित कई देशों में पवित्र स्थानों के दर्शन किए एवं भगवान् पशुपतिनाथ के चरणों में 500 क्विंटल चंदन की लकड़ी भेंट की। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए नाथू-ला दर्रा का खोला जाना तथा संयुक्त अरब अमीरात सरकार के सहयोग से अबू धाबी में भव्य मंदिर के निर्माण से यह पता चलता है कि पूरा विश्व अब भारतीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को कितने सम्मान एवं श्रद्धा से देखता है।

एक ओर जहां चोरी हुई प्राचीन कलाकृतियों– देवी-देवताओं की पवित्र मूर्तियों को देश में वापस लाने का कार्य हुआ है, वहीं दूसरी ओर 'हृदय' एवं 'प्रसाद' योजनाओं के अंतर्गत वैभवशाली विरासत को समेटे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्रों को भी भव्य एवं दिव्य बनाया जा रहा है। 'मां गंगा' को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लक्ष्य से चल रहे 'नमामि गंगे' योजना में अनेक यूरोपीय देश अपनी नवीनतम तकनीक के साथ सहयोग कर रहे हैं, ताकि गंगा का पवित्र एवं अविरल प्रवाह निरंतर देश की भूमि को तृप्त करता रहे। जहां कुंभ मेले को यूनेस्को ने मान्यता दी है, वहीं यह अत्यंत गौरव का विषय है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को द्वारा स्वीकारा गया है। चार धाम, राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट, पंचतीर्थ जैसे विशाल कार्य से देश सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक ऊर्जा प्राप्त कर शक्तिसंपन्न एवं सुदृढ़ बनेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि दासता के लंबे काल के कारण राष्ट्र का विश्वास अपनी स्वयं की रचनात्मकता एवं सर्जनात्मकता पर से डोल गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उठाए जा रहे कदमों से न केवल सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्रों की पुनर्प्रतिष्ठा एवं वैभव वापस आ रहे हैं, बल्कि नए आत्मविश्वास से भरा राष्ट्र 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जहां कांग्रेस एवं इसके सहयोगी संसद की गरिमा पर आघात करते हुए लोकतंत्र पर हमला बोल रहे हैं, वहीं देशभर में जनता मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे इन व्यापक परिवर्तनों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सांस्कृतिक केंद्रों के अभ्युदय से एक 'आत्मनिर्भर भारत' का उदय हो रहा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

‘श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर’ का लोकार्पण भारत को एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाएगाः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 दिसंबर, 2021 को वाराणसी में ‘दिव्य काशी, भव्य काशी’ कार्यक्रम के तहत ‘श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर’ का उद्घाटन किया। यह परियोजना पांच लाख वर्ग फुट में फैली हुई है, जो मंदिर परिसर को गंगा नदी से जोड़ती है और यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है। इस पवित्र नगरी में आगमन पर श्री मोदी ने सर्वप्रथम भगवान ‘काल भैरव’ से आशीर्वाद लिया और फिर पावन गंगा में डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की, जहां से उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए पवित्र जल लिया। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और उसके बाद इस परियोजना के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों पर पुष्पवर्षा कर उनका सम्मान किया। इसके बाद श्री मोदी ने इन श्रमिकों के साथ फोटो खिंचवाकर इस पल को यादगार बना दिया। देर शाम श्री मोदी ने ‘गंगा आरती’ में हिस्सा लिया। उन्होंने काशी में मुख्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य वरिष्ठ नेतागण तथा बड़ी संख्या में देश भर से आए संत शामिल हुए।

श्री मोदी के संबोधन की प्रमुख बातें

- ‘श्री विश्वनाथ धाम’ एक भव्य भवन भर नहीं है, यह प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का! यह प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का! यह प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परम्पराओं का! भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का
- पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वह अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं
- काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाएगा। यह परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं
- मेरे लिए जनता-जनार्दन ईश्वर का ही रूप है, हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है, मैं आपसे हमारे देश के लिए तीन संकल्प चाहता हूं— स्वच्छता, सृजन और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए निरंतर प्रयास
- गुलामी के लंबे कालखंड ने हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूं— पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, नवाचार करिए, अभिनव तरीके से करिए

'श्री विश्वनाथ धाम' भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 दिसंबर को वाराणसी में 'श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर' का लोकार्पण किया। उन्होंने काशी के काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम में पूजा-अर्चना की। श्री मोदी ने पावन गंगा नदी में पवित्र स्नान भी किया।

'नगर कोतवाल' (भगवान काल भैरव) के चरणों में प्रणाम के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ विशेष नहीं होता है। श्री मोदी ने देशवासियों के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने पुराणों का हवाला दिया, "जो कहते हैं कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा हमारे यहां आते ही हमारी अंतर-आत्मा को जागृत कर देता है।"

उन्होंने कहा कि श्री विश्वनाथ धाम का यह पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है। यह हमारे भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारी आध्यात्मिक आत्मा का प्रतीक है। यह भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि जब कोई यहां आएगा तो यहां न केवल आस्था बल्कि अतीत के गौरव को भी महसूस करेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीनता और नवीनता एक साथ कैसे जीवंत हो उठी है, प्राचीन की प्रेरणा भविष्य को कैसे दिशा दे रही है, इसके साक्षात दर्शन हम विश्वनाथ धाम परिसर में कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि पहले मंदिर का क्षेत्रफल केवल 3,000 वर्ग फीट तक सीमित था जो अब बढ़कर लगभग 5 लाख वर्ग फीट हो गया है। अब 50,000–75,000 श्रद्धालु मंदिर और मंदिर परिसर में दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब पहले मां गंगा के दर्शन और स्नान करें और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम पहुंच जाएं।

काशी के वैभव का जिक्र करते हुए श्री

मोदी ने कहा कि काशी स्थायी है और भगवान शिव के संरक्षण में है। उन्होंने इस भव्य परिसर के निर्माण में प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त किया। यहां तक कि उन्होंने कोरोना के दौरान भी यहां काम रुकने नहीं दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया।

श्री मोदी ने धाम के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ दोपहर का भोजन किया। प्रधानमंत्री ने कारीगरों, निर्माण से जुड़े लोगों, प्रशासन और उन परिवारों की भी सराहना की जिनके यहां पर घर थे। इन सबके साथ उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए लगातार कठोर परिश्रम करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी।

काशी वह है— जहां सत्य ही संस्कार है

श्री मोदी ने कहा कि आक्रमणकारियों ने इस शहर पर हमला किया, इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। यह शहर औरंगजेब के अत्याचारों और उसके आतंक के इतिहास का साक्षी है। जिसने तलवार से सभ्यता को बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से अलग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर औरंगजेब है, तो शिवाजी भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे भारत की एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं और ब्रिटिश काल में भी, हेस्टिंग्स का क्या हश्र काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग जानते ही हैं।

श्री मोदी ने काशी की महिमा और महत्व का वर्णन किया। उन्होंने टिप्पणी की कि काशी केवल शब्दों की बात नहीं है, यह संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वह है— जहां जागृति ही जीवन है; काशी वह है— जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वह है— जहां सत्य ही संस्कार है; काशी वह है— जहां प्रेम ही परम्परा है।

उन्होंने कहा कि वाराणसी वह शहर है जहां से जगद्गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा

प्रधानमंत्री ने गंगा आरती में भाग लिया और आधी रात को 'श्री काशी विश्वनाथ धाम', बनारस रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 दिसंबर की देर शाम 'गंगा आरती' में हिस्सा लिया। 'गंगा आरती' के समय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि काशी की आरती हमेशा मन को नई ऊर्जा से भर देती है। उन्होंने कहा कि काशी की गंगा आरती हमेशा अंतर्मन को नई ऊर्जा से भर देती है। आज काशी का बड़ा सपना पूरा होने के बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुआ और मां गंगा को उनकी कृपा के लिए नमन किया। नमामि गंगे तव पाद पंकजम्।

इसके बाद श्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मध्यरात्रि के बाद वाराणसी की सड़कों पर निकले और 'श्री काशी विश्वनाथ धाम' और बनारस रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहा हूं। इस ऐतिहासिक शहर के लिए हर संभव सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा तैयार करने का हमारा प्रयास है।

बाद में एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला पड़ाव...बनारस स्टेशन। हम रेल संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।

की पवित्रता से प्रेरणा मिली और उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। यह वह स्थान है जहां गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान शंकर से प्रेरणा लेकर रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। श्री मोदी ने कहा कि अगर समाज को जोड़ने करने की जरूरत पड़ी थी तो यह काशी संत रैदास जी की भक्ति की शक्ति का केन्द्र बनी।

श्री मोदी ने कहा कि काशी चार जैन तीर्थंकरों की भूमि है, जो अहिंसा और तपस्या का प्रतीक रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य, रामानंद जी के ज्ञान तक। चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास से लेकर स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय तक। काशी की पवित्र भूमि अनेक संतों, आचार्यों का घर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण यहां पड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, कई सेनानियों की कर्मभूमि-जन्मभूमि काशी रही है। उन्होंने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जैसी प्रतिभाएं इस महान शहर से हैं।

श्री मोदी ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को निर्णायक दिशा देगा और उज्ज्वल भविष्य का नेतृत्व करेगा। यह परिसर हमारी क्षमता और हमारे कर्तव्य का साक्षी है। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी की भुजाओं में अकल्पनीय को साकार करने का बल है। हम तप जानते हैं। तपस्या जानते हैं और देश के लिए दिन-रात खपना जानते हैं। कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, हम भारतीय हर चुनौती को एक साथ मिलकर परास्त कर सकते हैं।

अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है 'आज का भारत'

श्री मोदी ने कहा कि आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में माता अन्नपूर्णा खुद विराजती हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को अब एक शताब्दी के इंतजार के बाद काशी में फिर से स्थापित किया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए जनता-जनार्दन ईश्वर का ही रूप है, हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। उन्होंने लोगों से देश के लिए तीन संकल्प मांगे— स्वच्छता, सृजन और 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए निरंतर प्रयास।

श्री मोदी ने स्वच्छता को जीवन जीने का एक तरीका बताया और इस कार्य में विशेष रूप से 'नमामि गंगे' मिशन में लोगों की भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के लंबे कालखंड ने हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से मैं हर देशवासी का; पूरे आत्मविश्वास के साथ सृजन करने, नवाचार करने और अभिनव तरीके से काम करने का आह्वान करता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि तीसरा संकल्प जो आज लेने की जरूरत है, वह है 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि इस 'अमृत काल' में, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, हमें इस बात के लिए काम करना होगा कि जब भारत स्वतंत्रता के सौ वर्ष का उत्सव मनाएगा तो उस समय का भारत कैसा होगा। ■

जनता ने राज्य में कमल खिलाने का मन पहले ही बना लिया है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत 19 दिसंबर, 2021 को एक साथ 6 स्थानों— अंबेडकर नगर, मथुरा, बिजनौर, झांसी, बलिया और गाजीपुर से शुरू हुई। अंबेडकर नगर से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा को जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं झांसी में श्री राजनाथ सिंह ने, बिजनौर में श्री नितिन गडकरी ने, बलिया में श्री शिवराज सिंह चौहान ने, मथुरा में श्री योगी आदित्यनाथ ने और गाजीपुर में श्रीमती स्मृति ईरानी ने इस यात्रा को रवाना किया। जन विश्वास यात्रा 6 जगहों से शुरू होकर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के लगभग 4 करोड़ लोगों से सीधा संपर्क किया जाएगा और 'डबल इंजन' सरकार की उपलब्धियों को जनता के साथ साझा किया जाएगा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 दिसंबर, 2021 को अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने राज्य में कमल खिलाने का मन पहले ही बना लिया है। कार्यक्रम में भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर, श्री पंकज चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री सत्या कुमार, श्री अमरपाल मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेषनारायण मिश्र, उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्री विजय बहादुर पाठक, जिला भाजपा प्रभारी श्री विजय प्रताप सिंह एवं पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संजय मयूख भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करने के पश्चात् श्री नड्डा ने जन विश्वास यात्रा में भागीदारी की और कुछ दूर तक यात्रा के साथ चले।

प्रभु श्रीराम, भगवान् कृष्ण और महात्मा गौतम बुद्ध की धरती को नमन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि लोगों के बीच में जाना, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना और जनता से किये गए हर वादे को जमीन पर उतारकर दिखाना, देश के लोकतंत्र में यह कार्य-संस्कृति यदि किसी ने विकसित की है तो वह केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। पहले की संस्कृति तो ये थी कि लोगों को बांटकर वोट बटोरो, झूठे वादे कर जनता को गुमराह करो, जनता में वैमनस्य पैदा करो और भाई-भाई को लड़ाओ। यह भारतीय जनता पार्टी है जो समर्पित भाव से जनता की सेवा कर रही है। बाकी हर पार्टियां वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद के दंश से ग्रसित है।

उन्होंने कहा कि आजकल लोग नए-नए नारे गढ़कर नए-नए कलेवर में सामने आ रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सपा का कुशासन नहीं भूली है, सपा सरकार के समय का माफिया राज नहीं भूली है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं भूली है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि खनन माफिया, भू-माफिया और अपराधियों ने सपा सरकार के समय किस तरह पूरे प्रदेश को अपने गिरफ्त में ले लिया था। उन सभी माफियाओं और अपराधियों को जेल भेजने का और उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर खदेड़ने का काम योगी आदित्यनाथ ने

किया है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं और अपराधियों का सफाया किया है।

समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सपा और भ्रष्टाचार एवं अपराध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपा सरकार के समय गोमती रिवर फ्रंट और यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट में करोड़ों का घपला उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। लैपटॉप वितरण में भी सपा की अखिलेश सरकार ने बड़ा घपला किया था। कई रिपोर्टों के अनुसार सपा सरकार ने खरीदी तो 14 लाख लैपटॉप थी, लेकिन वितरण लगभग 6 लाख का ही हुआ। स्पष्ट है कि ये नई सपा नहीं है, वही सपा है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किये जाने की खबर पर समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह अनैतिक बयान दे रहे हैं और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है और तिस पर तुर्रा यह कि अखिलेश यादव ऐसे शर्मनाक बयानों का खुलकर बचाव कर रहे हैं! स्पष्ट है कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास को जमीन पर उतारा है और प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाया है। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास की बहार आई है। एक ओर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। एक ओर रामायण सर्किट का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर बुद्ध सर्किट का निर्माण हो रहा है। खुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कभी बीमारू प्रदेश की सूची में रहने वाला उत्तर प्रदेश अब देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा कर रहा है। साथ ही, यह निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के तौर पर भी उभर रहा है।

श्री नड्डा ने उत्तर प्रदेश की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि ज़िंदा समाज वह होता है जो अच्छे काम करने वाले लोगों को शाबाशी दे और काम न करने वाले लोगों को घर बिठाए। मुझे पूरा विश्वास है कि अवध की जनता काम न करने वाले लोगों को घर बिठाने का काम करेगी और विकास के प्रति समर्पित रहनेवाली भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को पुनः भारी बहुमत से विजयी बनाएगी।

झांसी

न बुआ चाहिए, न बबुआ, हमें केवल बाबा चाहिए : राजनाथ सिंह

जन विश्वास यात्रा के शुभारंभ समारोह में रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, "सीएम योगी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। मैं भी मुख्यमंत्री रहा, लेकिन योगी का नाम सुनते ही अपराधियों की धड़कन बढ़ जाती है। वह बल्लेबाजी तो करते ही हैं, जब गेंदबाजी पर उतरते हैं तो बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ देते हैं। उनकी इन स्विंगर और आउटस्विंगर के आगे सपा, बसपा और कांग्रेस टिक नहीं पाएगी।''

इसके साथ ही श्री सिंह ने नारा दिया, 'न बुआ चाहिए, न बबुआ, हमें केवल बाबा चाहिए।' उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2021 में बुंदेलखंड में अर्जुन बांध का लोकार्पण किया। इसके पहले सपा के लोगों ने ये नहीं होने दिया था। सपा ने बुंदेलखंड को प्यासा रखा, उन्हें इसका पाप लगेगा। इस पाप की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। केन-बेतवा लिंक के लिए 44 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आप ही बताइए यदि भाजपा नहीं होगी तो यह सब कौन करेगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री बी.एल. वर्मा, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री भानुप्रताप सिंह सहित अनेक नेतागण उपस्थित थे।

बिजनौर

भाजपा सरकार में सड़कों का कायाकल्प हो चुका है : नितिन गडकरी

जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने चांदपुर के गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज में हरी झंडी दिखाकर किया।

श्री गडकरी ने कहा, 'अभी चुनाव के महाभारत की शुरुआत होने वाली है। महाभारत ने सत्य-असत्य, नैतिकता-अनैतिकता के बीच फर्क का अंतर करना सिखाया है। आपको देश, समाज और कल्याण के नाम पर जाना है या गुंडागर्दी के नाम पर जाना है। सरकार जनता से है इसलिए चुनने का काम भी जनता को ही करना है। विजय तब होती है जब सत्य की विजय होती है।'

श्री गडकरी ने अपने भाषण में कहा, 'पहले की सरकारों में सड़क गड्ढे में होती थी और इस सरकार में सड़कों का कायाकल्प हो चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेरठ हाईवे का पूजन के लिए आने में साढ़े चार घंटे लग गए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरठ में 16 लेन का रोड बनाया है। दिल्ली से मेरठ केवल 45 मिनट में पहुंचने का मैं आपको वचन देता हूं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे।

बलिया

बबुआ की साइकिल भ्रष्टाचार और अन्याय से पंक्चर हो गई है : शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि जो लोग हिंदुत्व को सांप्रदायिक बताते थे, आज उन्हें ही हिंदुत्व भाने लगा है। राहुल बाबा राम-राम जप रहे हैं। जनेऊ पहन रहे हैं और त्रिपुंड लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी गंगा स्नान कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि बबुआ की साइकिल भ्रष्टाचार और अन्याय से पंक्चर हो गई है।

श्री चौहान ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज था, लेकिन अपराधी अब कहते हैं कि जेल में ही अच्छे हैं। ये साधारण परिवर्तन नहीं है। श्री चौहान ने वंशवाद पर भी कांग्रेस और सपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महत्वपूर्ण कुर्सी पर सिर्फ गांधी परिवार से और सपा में सिर्फ एक खास जाति से होते हैं। जबकि भाजपा में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है। भाजपा ने वंशवाद का नाश किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश से पड़ोसी उत्तर प्रदेश में मामा के धर्म से आया हूं। भाजपा को वोट दें।

मथुरा

'डबल इंजन' की सरकार आपको 'डबल डोज' देने का कार्य कर रही है : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर जनता से केंद्र और राज्य सरकार के विकास को आगामी चुनाव के लिए जन विश्वास में बदलने की अपील की।

बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी धाम में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रमिकों पर की गई पुष्प वर्षा को उन्होंने अपने लिए आनंद की अनुभूति बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रयागराज कुंभ में स्वच्छकारों के पैर धोए थे। कभी ऐसा हुआ है!

जन विश्वास रथ यात्रा के दौरान श्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के बाद उपस्थित जनसमुदाय से सवाल भी पूछे कि क्या सपा की सरकार होती तो वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, बलदेव, गोकुल तीर्थ स्थल घोषित होते। क्या मथुरा में मदिरा-मांस की बिक्री बंद होती। भगवान श्रीराम का मंदिर अयोध्या में बनता, क्या गरीबों को राशन फ्री दे पाते, फ्री वैक्सीन मिल मिल पाती। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपको डबल डोज देने का कार्य कर रही है। इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री सर्वश्री महेंद्र नाथ पांडेय एवं अर्जुनराम मेघवाल, सांसद श्री राजवीर सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

गाजीपुर

गुंडे-मवालियों को जेल भेजा योगी सरकार ने : स्मृति ईरानी

केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने लंका मैदान से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पूर्व उन्होंने लंका मैदान में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।

उन्होंने भारत माता की जय से अपने उद्बोधन का शुभारंभ करते हुए गाजीपुर की बलिदानी धरती को प्रणाम किया और कहा कि यह यात्रा जहां से गुजरे तो याद दिलाओ कि भूलना मत वो मंजर जब साइकिल के साथ वो हाथ का पंजा जुड़ा था और वो हाथ हमारी मां-बहनों का आंचल उड़ाया करता था। भूलना मत उत्तर प्रदेश का वो मंजर जब गरीब की बेटियों पर लाठी चलाई जाती थी और वो सरकारी नौकरी चाहते थे। भूलना मत वो मंजर जब किसान खाद के लिए लड़ता था और किसानों पर लाठी चलाने से सपा का कोई भी नेता डरता नहीं था। भूलना मत, गरीबों को लूट-लूट कर गुंडे-माफिया अपना आलीशान महल बनाते थे।

उन्होंने कहा कि माफिया के लूट पर बुल्डोजर चला। कार्रवाई गुंडों के खिलाफ हुई क्योंकि जनता चाहती थी। आज अब्दुल हमीद की पुण्य धरती से कह रही हूं; गुंडे-मवालियों को जेल भेजा योगी सरकार ने, क्योंकि जनता चाहती थी। उन्होंने कोरोना काल में केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि यह रिकार्ड है कि मोदी सरकार ने 19 महीने तक 80 करोड़ जनता के घर मुफ्त में राशन भिजवाया। ■

'राज्य में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है'

गत 18 दिसंबर, 2021 से हरिद्वार (उत्तराखंड) से शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा 5 जनवरी, 2022 तक चलेगी और राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों से होते हुए 4500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें गढ़वाल मंडल में 2660 और कुमाऊं मंडल में 1890 किमी की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से भाजपा केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा लेकर जनता के बीच जाएगी। इस यात्रा के दौरान जगह-जगह सभाएं, रोड शो जैसे कार्यक्रम होंगे। कई केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय नेता समय-समय पर इस यात्रा में भागीदारी करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 दिसंबर, 2021 को हरिद्वार (उत्तराखंड) के पंतदीप मैदान में वेदपाठ और शंखनाद के साथ प्रदेश भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सर्वश्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, हरिद्वार से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिश्वरानंद के साथ-साथ राज्य सरकार के कई मंत्री, भाजपा विधायक एवं भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। विकास संकल्प यात्रा को रवाना करते हुए उन्होंने हरिद्वार में एक भव्य रोड शो किया। खराब मौसम और कड़ाके की सर्दी होने के बाद भी पार्टी कार्यकर्ता और हरिद्वार के कोने-कोने से जनता इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। पूरा हरिद्वार शंखनाद और भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो रहा था और हर जगह केवल कमल ही कमल नजर आ रहा था।

श्री नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। पिछले पांच वर्षों में उत्तराखंड में केंद्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। श्री केदार धाम में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। चार धामों को कनेक्ट करने वाली ऑल वेदर रोड का निर्माण भी अंतिम चरण में है।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला वीर जवानों की भी भूमि है। 1972 से 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग लंबित थी लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे लागू करने की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने 'वन रैंक, वन पेंशन' योजना को लागू किया और अब तक इसके तहत लगभग 48,000 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। उत्तराखंड में भी डेढ़ लाख से अधिक फौजी परिवारों को इसका लाभ पहुंचा है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाया है। चाहे राफेल का बेड़ा लाना हो, चिनूक और होवित्जर की तैनाती हो, सर्फेस टू एयर मिसाइल की तैयारी हो या सेना को आधुनिक साजो-सामान की आपूर्ति, हर क्षेत्र में कई गुना आगे बढ़ कर कार्य हुआ है।

श्री नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में ढाई सौ की आबादी वाले गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड की पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है, इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। हरिद्वार और हल्द्वानी में रिंग रोड का कार्य चल रहा है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम के तहत कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हरिद्वार और देहरादून में पाइप के जरिए घर-घर गैस पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। उत्तराखंड में कई बड़े शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से उत्तराखंड में ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और एनसीसी की एकेडमी की स्थापना हो रही है। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। ■

विकास के प्रति समर्पित योगी सरकार के गठन का मार्ग पुनः प्रशस्त करें : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 17 दिसंबर, 2021 को लखनऊ में रमा बाई आंबेडकर मैदान में निषाद समाज और भाजपा की पहली संयुक्त महारैली को संबोधित किया और राज्य की जनता से निषाद पार्टी-भाजपा के एनडीए गठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। रैली को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह सहित कई सांसद, प्रदेश के मंत्री, विधायक और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज को नमन करते हुए श्री शाह ने अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 2019 में श्री संजय निषाद भाजपा के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर बूथ पर कमल का संदेश लेकर पहुंचे। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को आशातीत सफलता मिली और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में 300 से अधिक सीटों पर जीत के साथ भाजपा की भव्य विजय हुई।

उन्होंने कहा कि वर्षों से मांग थी कि मछुआरे भाइयों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाय। 2019 के चुनाव में श्री संजय निषाद और साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्रीजी से एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग की। तब प्रधानमंत्रीजी ने इसे बनाने का वादा किया और आज अलग मंत्रालय बनकर यह हमारे सामने है। इस मंत्रालय के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाएं इम्प्लीमेंट हुई हैं।

उन्होंने कहा कि सपा और बसपा अपने-आप को पिछड़ों की पार्टी होने का दावा करती है, वह केंद्र में लगातार कांग्रेस की सरकारों का समर्थन करती रही, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का कार्य किसी ने भी नहीं किया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी।

2019 के चुनाव में श्री संजय निषाद और साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्रीजी से एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग की। तब प्रधानमंत्रीजी ने इसे बनाने का वादा किया और आज अलग मंत्रालय बनकर यह हमारे सामने है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 से 2019 तक लगभग 5,000 करोड़ रुपये की निधि से नीली क्रांति योजना की शुरुआत की। साथ ही, 7,522 करोड़ रुपये के जलीय कृषि बुनियादी ढांचे की शुरुआत हुई। तीन करोड़ से अधिक मछुआरे भाइयों के कल्याण के लिए नए मत्स्य विभाग का गठन किया गया। इसके इन्फ्रॉस्ट्रक्चर के लिए लगभग 7000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी मत्स्य से जुड़े व्यापार और कारोबार के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया। प्रदेश में मत्स्य बीज के उत्पादन के लिए लगभग 1191 करोड़ रुपए से अधिक निवेश हुआ है। लगभग 5900 से अधिक मछुआरे भाइयों को क्रेडिट कार्ड मिल चुका है और बाकी लोगों को अगले साल में क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तालाबों/पोखरों के पट्टे के आवंटन की भी व्यवस्था हुई है। विपक्ष पर हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा की सरकारें माफिया का संरक्षण करती रहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार में माफिया और गुंडे पलायन करने पर विवश हैं।

उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब निषाद पार्टी और भाजपा के गठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाएं और विकास के प्रति समर्पित भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार की सरकार के गठन का मार्ग पुनः प्रशस्त करें। ■

'हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं, वे दंगातंत्र के पुजारी हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 दिसंबर, 2021 को मेरठ में लगभग 23 हजार बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया और उन्हें आगामी उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के संदर्भ में जीत के मंत्र दिए। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सर्वश्री स्वतंत्र देव सिंह, उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव सह-प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु, संगठन महामंत्री कर्मवीर, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, संजीव बालियान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काम देखनेवाले संजय भाटिया और क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, क्षेत्र के सांसद, प्रदेश और क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि बाकी दलों की जनसभा में जितनी संख्या होती है, उससे कहीं अधिक कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में होते हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी है जहां गरीब से गरीब परिवार से आने वाले कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम और मेधा के बल पर पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर सकते हैं। बाकी सभी पार्टियों में एक विशेष परिवार में बेटा, भतीजा या चाचा होना जरूरी है। अब तो इन पार्टियों में वंशवाद इतना मजबूत हो चुका है कि चाचा भी किनारे कर दिए जा रहे हैं।

यह भारतीय जनता पार्टी है जहां गरीब से गरीब परिवार से आने वाले कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम और मेधा के बल पर पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर सकते हैं

समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा प्रहार करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सपा के नेता अपना पुराना चेहरा ढ़ककर नए चेहरे में आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है। अखिलेश सरकार में 15 आतंकी पकड़े गए थे, तब सपा सरकार ने ये कहकर इन आतंकियों को छुड़ा लिया कि ये दोषी नहीं हैं। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन आतंकियों को फिर से गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकद्दमा चला और वे दोषी करार दिए गए। इनका गुनाह इतना संगीन था कि इनमें से चार को फांसी हुई और कई को उम्रकैद हुई। ये वंशवाद प्रोडक्ट का जीता-जागता उदाहरण है कि किस तरह ये राष्ट्र हित को वोट की खातिर बेच डालते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को यह भी याद होगा कि किस तरह अखिलेश सरकार में प्रदेश के पूर्व डीजीपी और उनके साथ दर्जनों लोगों पर फर्जी तरीके से फंसाया गया, उन पर मुकद्दमे चलाये गए। उसके खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी और न्याय की जीत हुई। हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं, वे दंगातंत्र के पुजारी हैं। अखिलेश सरकार में 700 से अधिक दंगे हुए, 100 से अधिक लोगों ने इन दंगों में अपनी जानें गंवाईं। हमें 27 अगस्त, 2013 को शुरू हुआ मुजफ्फरनगर का दंगा भी याद है। हमें यह भी याद है कि किस तरह सचिन और गौरव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और फिर आरोपियों को अखिलेश सरकार ने छुड़ाया था। आज उत्तर प्रदेश में हर जगह शांति है, कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव नहीं है और विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। याद कीजिये कैराना की घटना, याद कीजिये अखिलेश सरकार में पलायन का दौर, याद कीजिये मुजफ्फरनगर के दंगे– यही तो है दंगा तंत्र। इस दंगा तंत्र को ख़त्म कर योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रजातंत्र की नींव पर अंत्योदय के सिद्धांत पर सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी विकास का नया अध्याय शुरू किया है।

श्री नड्डा ने कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है। अब तक गन्ना किसानों को अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के समय का भी बकाये का लगभग 11,000 करोड़ रुपये भुगतान किसानों को किया है। बसपा की सरकार और अखिलेश की सपा सरकार ने अपने शासनकाल में किसानों को जितना गन्ने का भुगतान किया था, उससे कहीं अधिक भुगतान भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार में हुआ है। सपा-बसपा और कांग्रेस पर बरसते हुए श्री नड्डा ने कहा कि गन्ना का भुगतान हमारी विकास की नीति को रेखांकित करता है, जबकि जिन्ना उनकी राजनीति का आधार

है। हम गन्ने पर भी चुनाव लड़कर जनता का विश्वास जीतेंगे और जिन्ना वाली मानसिकता पर भी विजय प्राप्त करेंगे। मायावती सरकार के शासनकाल में लगभग 19 चीनी मिलें बंद हो गई और कई चीनी मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गईं। अखिलेश सरकार के समय भी लगभग 11 चीनी मिलें बंद हुईं लेकिन चीनी मिलों के खुलने का काम योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार के समय शुरू हुआ है, हमारी सरकार में यूपी में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए व्यापक सुधार की चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास को एक नया आयाम दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, गंगा लिंक एक्सप्रेस-वे, बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर जैसे अनेक उदाहरण इसकी बानगी है। आज उत्तर प्रदेश का बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये है जो सर्वाधिक है। योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश में लगभग 86 लाख किसानों के लगभग 36,000 रुपये का कृषि ऋण माफ़ हुआ है। ■

बूथ अध्यक्षों से संवाद, एटा

'हर बूथ पर कमल खिलाना जरूरी है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने उत्तर प्रदेश प्रवास के दूसरे दिन 12 दिसंबर, 2021 को एटा में ब्रज क्षेत्र के लगभग 28,222 बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया और उन्हें विधान सभा चुनाव के मद्देनजर जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती बेबी रानी मौर्य, केंद्रीय मंत्री सर्वश्री अर्जुन राम मेघवाल, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल और राज्य सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा एवं क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राजवीर सिंह सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, क्षेत्र के सांसद, प्रदेश और क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

विपक्ष पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि किसानों का नेता होने का दावा करने वाले तो कई हुए लेकिन इन लोगों ने किसानों के नाम पर केवल नेतागिरी की, उनका भला नहीं किया। किसानों का कल्याण हुआ और कृषि का विकास हुआ तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में। कांग्रेस की सरकार में केवल एक बार किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, वह भी केवल 57,000 करोड़ रुपये, जबकि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के बैंक एकाउंट में केवल एक योजना (किसान सम्मान निधि) में ही 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि पहुंचा दी है। भारत सरकार प्रति बोरी डीएपी पर 1200 रुपये की सब्सिडी दे रही है जिसके चलते 2400 रुपये की बोरी किसानों को महज 1200 रुपये में मिल रही है। करोड़ों किसान फसल बीमा योजना और स्वायल हेल्थ कार्ड योजना से लाभान्वित हुए हैं। किसान मानधन योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से हर खेत तक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और खेत से लेकर खलिहान तक फसल सुरक्षा कवच तैयार किया गया है।

> **कांग्रेस की सरकार में केवल एक बार किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, वह भी केवल 57,000 करोड़ रुपये जबकि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के बैंक एकाउंट में केवल एक योजना (किसान सम्मान निधि) में ही 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि पहुंचा दी है**

उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री था तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से एटा में मेडिकल कॉलेज दिया गया। यूपी में दो-दो एम्स बनाए गए, कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में अब तक 30 मेडिकल कॉलेज बनाए जा चुके हैं और अगले साल तक ये बढ़कर 42 हो जायेंगे। अब उत्तर प्रदेश में स्टेट-वे की बजाय एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क बिछाया जा चुका है। कई रूट्स पर मेट्रो का काम शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत, आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना– ये सभी उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश स्तर पर भी कई लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुरुआत की है जिसके बल पर उत्तर प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार में डबल लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त और माफिया मुक्त राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऐसे लोगों को घर बिठाना और हर बूथ पर कमल खिलाना जरूरी है। ■

अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में 29 प्रतिशत की भारी वृद्धि

आईटी/बीपीओ क्षेत्र में 152 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई, जबकि स्वास्थ्य में 77 प्रतिशत, शिक्षा में 39 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग में 22 प्रतिशत, परिवहन में 68 प्रतिशत और निर्माण में 42 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई

अप्रैल से जून, 2021 की अवधि के लिए तिमाही रोजगार सर्वे (एक्यूईईएस) के पहले दौर के परिणाम के अनुसार छठी आर्थिक गणना (2013-14) के 9 चुनिंदा क्षेत्रों के सामूहिक 2.37 करोड़ की तुलना में नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.08 करोड़ हो गया। इस तरह रोजगार में 29 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई। आईटी/बीपीओ क्षेत्र में 152 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई, जबकि स्वास्थ्य में 77 प्रतिशत, शिक्षा में 39 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग में 22 प्रतिशत, परिवहन में 68 प्रतिशत और निर्माण में 42 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यह जानकारी 20 दिसंबर को लोकसभा में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली ने दी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल भारतीय तिमाही प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वे (एक्यूईईएस) लॉन्च किया था।

वार्षिक सावधिक श्रम शक्ति सर्वे (पीएलएफएस) के अनुसार देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 6, 2018-19 में 5.8 और 2019-20 में 4.8 है।

सरकार की प्राथमिकता रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजन के लिए कौशल में सुधार करना है। इसी के अनुसार भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। भारत सरकार ठोस निवेश तथा सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है। इनमें सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) हैं।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहित करने और कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अंतर्गत सरकार 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन दे रही है। भारत सरकार की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (पीएमजीकेवाई) ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत भारत 12 प्रतिशत नियोक्ता के शेयर और 12 प्रतिशत कर्मचारी के शेयर का योगदान दिया है। यह 15 हजार रुपये से कम आय वाले 90 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ 100 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए मार्च से अगस्त, 2020 के वेतन का कुल 24 प्रतिशत है।

सरकार ने रोजगार को प्रोत्साहित करने तथा घर से वापस आये श्रमिकों और 6 राज्यों— बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 चुनिंदा जिलों में युवाओं सहित समान रूप से प्रभावित व्यक्तियों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) लॉन्च किया। इस अभियान से 50.78 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार सृजन हुआ।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के भाग के रूप में 1 अक्तूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) लांच की गई। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नये रोजगारों का सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को संवेदी बनाना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू की जा रही है, इसका उद्देश्य नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अधिक श्रमिकों को रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 तक कर दी गई है। 1.17 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.59 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों को कामकाजी पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 1 जून, 2020 को लॉन्च की गई। ऐसे स्ट्रीट वेंडरों के व्यवसाय पर कोविड-19 के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस योजना के अंतर्गत 26.46 लाख लाभार्थियों को 2641.46 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

स्वरोजगार में सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) लागू की जा रही है। इसमें सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियां तेज करने या बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत 31.28 करोड़ ऋण नवम्बर, 2021 तक मंजूर किए गए हैं।

इन पहलों के अतिरिक्त मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन, सभी के लिए आवास, आधारभूत संरचना विकास, औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) जैसे सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों का उद्देश्य भी उत्पादक रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। ■

सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के व्यापक कार्यक्रम को मिली मंजूरी

यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के उत्पादन में उच्च घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा और 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान देगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर को भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से देश में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन के क्षेत्र में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह सामरिक महत्व तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के प्रौद्योगिकीय नेतृत्व के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई, स्पेक्स योजना तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के लिए पीएलआई के तहत 55,392 करोड़ रुपये (7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की प्रोत्साहन सहायता राशि को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, एसीसी बैटरी, ऑटो घटकों, दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों, सौर पीवी मॉड्यूल एवं व्हाइट गुड्स सहित संबद्ध क्षेत्रों के लिए 98,000 करोड़ रुपये (13 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की पीएलआई प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई हैं। कुल मिलाकर, भारत सरकार ने आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में देश को सेमीकंडक्टरों वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 2,30,000 करोड़ रुपए (30 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की सहायता दी है।

उपर्युक्त कार्यक्रम का उद्देश्य सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टरों/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग (एटीएमपी/ओएसएटी), सेमीकंडक्टर डिजाइन के काम में लगी हुई कंपनियों/संघों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है।

सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं, जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले प्रणालियों का उत्पादन बहुत जटिल तथा प्रौद्योगिकी की अधिकता वाला क्षेत्र है, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि और पेबैक अवधि तथा प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव शामिल हैं और इसके लिए अत्यधिक एवं निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। यह कार्यक्रम पूंजी सहायता और प्रौद्योगिकीय सहयोग की सुविधा प्रदान करके सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले प्रणाली के उत्पादन को बढ़ावा देगा।

वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले के विश्वसनीय स्रोत रणनीतिक महत्व रखते हैं तथा महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। स्वीकृत कार्यक्रम भारत की डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा तथा घरेलू क्षमताओं का निर्माण करेगा। यह देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए अत्यधिक कुशल रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले प्रणाली के विकास का वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ गहन एकीकरण के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के उत्पादन में उच्च घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा और 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ■

राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक लग चुके हैं 142.47 करोड़ से अधिक टीके

भारत का राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण 28 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार 142.47 करोड़ (1,42,46,81,736) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,51,91,424 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया। महामारी की शुरुआत के बाद से देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,42,43,945 हो गई है।

नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.40 % है। मार्च, 2020 के बाद से ये अधिकतम है। वर्तमान में 75,456 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.22 प्रतिशत हैं। यह मार्च, 2020 के बाद से सबसे कम है। भारत ने अब तक कुल 67.41 करोड़ (67,40,78,531) जांच की है। ■

नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि पी' का सफल परीक्षण

'अग्नि पी' डुअल रिडनडेंट नेविगेशन तथा मार्गदर्शन प्रणाली के साथ एक दो चरणों वाली केनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इस उड़ान परीक्षण ने प्रणाली में एकीकृत सभी उन्नत प्रौद्योगिकियों के भरोसेमंद प्रदर्शन को साबित किया है

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 18 दिसंबर, 2021 को ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि पी' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। विभिन्न टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल स्टेशन और पूर्वी तट के साथ स्थित डाउन रेंज जहाजों ने मिसाइल ट्रेजेक्टरी और मानकों को ट्रैक किया तथा उनकी निगरानी की। इस मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने लक्ष्य का अनुसरण किया।

'अग्नि पी' डुअल रिडनडेंट नेविगेशन तथा मार्गदर्शन प्रणाली के साथ एक दो चरणों वाली केनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इस दूसरे उड़ान परीक्षण ने प्रणाली में एकीकृत सभी उन्नत प्रौद्योगिकियों के भरोसेमंद प्रदर्शन को साबित किया है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी और प्रणाली के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने कई अतिरिक्त विशेषताओं के साथ दूसरी विकास उड़ान परीक्षण करने के लिए टीम

के प्रयासों की सराहना की तथा एक ही कैलेंडर वर्ष के भीतर लगातार सफलता के लिए बधाई दी। ■

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 60% से अधिक की तीव्र गति से बढ़ा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 16 दिसंबर, 2021 तक के प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में 5,87,702.9 करोड़ रुपये की तुलना में जारी वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9,45,276.6 करोड़ रुपये है जो 60.8% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में (16.12.2021 तक) कुल संग्रह ने वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि के कुल संग्रह पर 40% की वृद्धि दर्ज की है, जब कुल संग्रह 6,75,409.5 करोड़ रुपये हुआ था और वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि के कुल संग्रह 6,70,739.1 करोड़ रुपये पर 40.93% की वृद्धि दर्ज की है।

कुल 9,45,276.6 करोड़ रुपये (16.12.2021 तक) के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 5,15,870.5 करोड़ रुपये (कुल रिफंड) निगम कर (सीआईटी) और सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) सहित 4,29,406.1 करोड़ रुपये (कुल रिफंड) का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 (16.12.2021 तक) के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (रिफंड के लिए समायोजन से पहले) पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में कुल 7,33,715.2 करोड़ रुपये की तुलना में 10,80,370.2 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के लिए सकल संग्रह 8,34,398 करोड़ रुपये और वह वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सकल संग्रह 7,96,342 करोड़ रुपये था।

कुल 10,80,370.2 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 6,05,652.6 करोड़ रुपये का निगम कर (सीआईटी) और सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) सहित 4,74,717.6 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है। लघु शीर्षवार संग्रह (16.12.2021 तक) में 4,59,917.1 करोड़ रुपये का अग्रिम कर, 4,93,171.7 करोड़ रुपये स्रोत पर कर कटौती (टीडीसी), 74,336.2 करोड़ रुपये का स्व-मूल्यांकन कर, 44,028.7 करोड़ रुपये का नियमित मूल्यांकन कर, 6,525.9 करोड़ रुपये का लाभांश वितरण कर और अन्य मामूली शीर्षों के तहत 2390.6 करोड़ रुपये का कर शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए 16.12.21 तक संचयी अग्रिम कर संग्रह 4,59,917.1 करोड़ रुपए है जबकि इसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 की इसी अवधि के लिए यह 2,99,620.5 करोड़ रुपये थी। इस पर वर्ष 2020-21 का अग्रिम कर संग्रह 53.5% (लगभग) की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, 16.12.2021 (वित्त वर्ष 2021-22) को 4,59,917.1 करोड़ रुपये का संचयी अग्रिम कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में इसी अवधि में अग्रिम कर संग्रह (संचयी) 3,18,929.4 करोड़ रुपये की तुलना में 44.21% की वृद्धि दर्शाता है और वित्त वर्ष 2018-19 में इसी अवधि में अग्रिम कर संग्रह (संचयी) 3,07,096.3 करोड़ रुपये पर 49.76% की वृद्धि दर्शाता है। ■

सिद्धांत और नीतियां

पं. दीनदयाल उपाध्याय

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

(गतांक से...)

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्र की सीमाओं का व्याप, उनकी स्थिति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, पड़ोसियों की नीति और तैयारी का ध्यान रखकर सुरक्षा बल की सभी शाखाओं का पर्याप्त विकास कर उन्हें आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया जाए।

देश की अर्थनीति और विदेश नीति के निर्धारण में सुरक्षा की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाए। राष्ट्र को मानसिक एवं शारीरिक, दोनों दृष्टियों से सुरक्षा सन्नद्ध करने के लिए जनसंघ निम्नलिखित कदम उठाना आवश्यक समझता है-

1. राष्ट्र के युवकों के लिए दो वर्ष की अनिवार्य सैनिक भरती।
2. सुरक्षा सेनाओं की सभी शाखाओं का स्वरूप और अंतःस्फूर्ति दोनों दृष्टियों से पूर्ण भारतीयकरण।
3. रक्षा संबंधी उद्योगों का पर्याप्त विकास।
4. परमाणु अस्त्रों का निर्माण।
5. एक विशाल प्रादेशिक सेना का संगठन।

सीमांत क्षेत्रों का विकास

सीमांत क्षेत्रों के विकास की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए तथा वहां के निवासियों को पूर्णतः सुसज्जित किया जाए, जिससे वे एक दृढ रक्षापंक्ति का काम कर सकें तथा सीमा के छोटे-मोटे उल्लंघनों को रोक सकें। पाकिस्तान से लगी सीमा के क्षेत्रवासी पाकिस्तान की घुसपैठ की योजनाओं को निष्फल करने में समर्थ हो सकें, इस दृष्टि से उस क्षेत्र की रचना की जाए।

भाषा नीति

भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। वे भारतीय जीवन की आधारभूत एकता की अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम रही हैं। उनमें कोई प्रकृति भेद नहीं है, प्रत्युत उनका संस्कृत के साथ आधारभूत संबंध होने के कारण तथा समान विचारधारा, समान धर्म, समान ज्ञान-विज्ञान होने के कारण उनकी एक बड़ी समान शब्दावली है तथा एक ही समाज की भावनाओं की अभिव्यक्ति के कारण उनके साहित्य की आत्मा एक है। पश्चिम के ज्ञान और विज्ञान को प्रकट करने के लिए आज सभी भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावली के सृजन की आवश्यकता है। केंद्र के निर्देशन में समान शब्दावली का निर्माण इस कार्य को सुकर बनाएगा तथा इन भाषाओं के स्वरूप की निकटता को आगे बढ़ाएगा।

शासन और शिक्षा, उद्योग और व्यापार सभी क्षेत्रों में स्वभाषाओं का प्रयोग स्वराज्य की स्वाभाविक परिणति है। राष्ट्रीय मनीषा को प्रकट करनेवाले जन-व्यवहार तथा जन आंदोलनों के परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं के प्रयोग क्षेत्र का एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में विकास हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। शासन एवं शिक्षा के क्षेत्र की भाषा नीति का निर्धारण इसी आधार पर होना चाहिए।

राष्ट्रभाषा संस्कृत

संस्कृत सदैव से भारत की राष्ट्रभाषा रही है। संस्कृत को इस रूप में मान्यता मिलनी चाहिए तथा विशेष संस्कार के अवसरों पर उसका प्रयोग करना चाहिए।

राजभाषा

भारत की भाषाओं में हिंदी ही सर्वाधिक समझी जानेवाली तथा पिछले अनेक वर्षों अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकासमान भाषा है। संविधान ने उसे केंद्रीय भाषा के रूप में अंगीकार कर इस तथ्य को स्वीकार किया है। देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग केंद्रीय राजभाषा के रूप में होना चाहिए।

विभिन्न प्रदेशों में वहां की भाषाएं राज-काज में प्रयुक्त होनी चाहिए। केंद्रीय शासन के जिन विभागों का जनता के साथ सीधा संबंध है, वहां क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार हो।

भारतीय भाषाओं के राजभाषा के रूप में व्यवहार के कारण राजसेवा में भरती तथा पदोन्नति के संबंध में उन व्यक्तियों के मन में आशंकाएं पैदा हो सकती हैं, जिनको इन भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अंतरिम काल के लिए उन्हें इस विषय में आश्वस्ति देनी चाहिए।

अनुसूचित भाषाएं

भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। अतः भारत के किसी भी भू-भाग में किसी भी अनुसूचित भाषा में प्रशासनाधिकारियों को आवेदन देने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सिंधी का अनुसूचित भाषाओं में समावेश हो।

उर्दू अलग भाषा न होकर हिंदी की एक शैली है, जिसका साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसके विकास के लिए आवश्यक है कि वह नागरी लिपि में लिखी जाए।

संविधान में अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त भी भारत में अनेक लोकभाषाएं हैं। इनका विकास तथा संबंधित क्षेत्रीय भाषा के साथ उनका निकट का संबंध दोनों के लिए पोषक होगा तथा हमारे साहित्य को सही अर्थ में जनजीवन का आदर्श बनाएगा।

शिक्षा

शिक्षा व्यक्ति का सामाजिक अधिकार है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज के साथ एकात्म होता है तथा अपने व्यक्तित्व की साधना के मार्ग तथा लक्ष्य को पाता है। शिक्षा के सहारे मानव की अद्यतन संचित ज्ञाननिधि हस्तांतरित होती है। इस पूंजी को लेकर ही मानव समष्टि को अपना योगदान करता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह अपनी वृत्ति का अनुपालन करता हुआ राष्ट्र के एक उत्तरदायी एवं संवेदनशील घटक के के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। साक्षरता, पुस्तक ज्ञान तथा तंत्रपटुता के साथ शारीरिक शक्ति का विकास, बुद्धि उद्बोधन, शील-संवर्धन, आदर्शों का प्रतिस्थापन, सामाजिकता एवं शिष्टाचार का स्वभाव-निर्माण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। स्पष्ट है कि यह शिक्षा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से अलग हटकर नहीं दी जा सकती। इस दृष्टि से शिक्षा के भारतीयकरण तथा अभिनवीकरण की आवश्यकता है, जिसकी कमी का अनुभव बहुत दिनों से व्यापक रूप से होते हुए भी उसे पूरा करने के लिए कोई क़दम नहीं उठाए गए।

शिक्षा व्यक्ति का सामाजिक अधिकार है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज के साथ एकात्म होता है तथा अपने व्यक्तित्व की साधना के मार्ग तथा लक्ष्य को पाता है

शिक्षा व्यवस्था

प्रजा को शिक्षा की उपेक्षा न करने देना, शिक्षा संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करना, प्रत्येक स्थान पर विद्वान् गुरुओं का प्राचुर्य रखना, देशकाल निमित्तों को शिक्षा के अनुकूल रखना, स्थान-स्थान पर शिक्षाश्रमों की व्यवस्था करना, स्नातकों एवं आचार्यों का योगक्षेम करना, सर्वतः उनके उत्साह को बढ़ाए रखना राज्य के परंपरागत कर्तव्य हैं।

राज्य की शिक्षा नीति का निम्नलिखित लक्ष्य होना चाहिए

1. माध्यमिक स्तर तक प्रत्येक बालक और बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध। यह स्तर इतना हो कि व्यक्ति विषयों के सामान्य ज्ञान के साथ आवश्यकतानुसार जीविकोपार्जन की क्षमता प्राप्त कर सके।
2. उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के शिक्षण की उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था।

स्वायत्त शिक्षा

शिक्षा का व्यय राज्य द्वारा वहन होने के उपरांत भी उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध करने के लिए शिक्षकों तथा शिक्षाविदों के स्वायत्त निकाय होने चाहिए। सरकार के विभाग के रूप में उनका चलाना ठीक नहीं। सरकारी और ग़ैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं का भेद समाप्त कर देना चाहिए। सभी क्षेत्रों के शिक्षकों के वेतनक्रम एवं अन्य सुविधाएं ऐसी हों, जिससे योग्य व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आने में संकोच न करे। शिक्षा संस्थाओं को मैनेजरों अथवा प्रबंध समिति की निजी संपत्ति बनने देना उचित नहीं।

शिक्षा समाज में भेद निर्माण करनेवाली न होकर उसमें एकात्म भाव निर्माण करनेवाली हो। भारत के 'पब्लिक स्कूल' इस उद्देश्य के प्रतिकूल हैं। आवश्यकता है कि सभी शिक्षण संस्थाओं का स्तर ऊंचा उठाया जाए।

शिक्षा का माध्यम

स्वभाषा के बिना जनता का विकास संभव नहीं है। जब तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाता, तब तक न तो हम सभी जनों को साक्षर और शिक्षित कर सकेंगे और न उस पैमाने पर तंत्र एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ उत्पन्न कर सकेंगे, जिनकी हमारी विकास योजनाओं को आवश्यकता है। मौलिक चिंतन तथा खोज तो परायी भाषा द्वारा प्राप्त ज्ञान में सहज संभव ही नहीं।

जनसंघ अंग्रेज़ी या अन्य विदेशी भाषाओं का विरोधी नहीं। दुनिया के विभिन्न देशों के साथ संपर्क बढ़ाने तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए हमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, स्पैनिश, जापानी, स्वाहिली, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का अध्ययन करना होगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी के प्रभुत्व एवं एकाधिकार ने हमें इन भाषाओं से भी दूर कर दिया है। फलतः आज हम दुनिया को अंग्रेजी भाषा-भाषी जगत् के चश्मे से ही देख रहे हैं। अंग्रेजी हमको दुनिया के साथ जोड़नेवाली कड़ी नहीं, बल्कि बहुत बड़े भाग से तोड़नेवाली कड़ी सिद्ध हो रही है।

शिक्षा क्षेत्र में भाषा के संबंध में यह नीति होनी चाहिए—

1. प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए।
2. माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम से दी जाए और हिंदी का अध्ययन अनिवार्य हो।
3. हिंदीभाषी विद्यार्थियों के लिए किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान आवश्यक हो।
4. राष्ट्र-भाषा संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य हो।

जहां क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा के विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या हो, वहां उस भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हिंदी माध्यम से पढ़ानेवाली शिक्षण संस्थाओं की देश भर में व्यवस्था हो।

(क्रमशः...)

भगवत शरण माथुर नहीं रहे

मध्यप्रदेश में भाजपा के पूर्व सह महामंत्री (संगठन) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री भगवत शरण माथुर का 14 दिसंबर को भोपाल में निधन हो गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तालेन गांव में जन्मे श्री माथुर 70 वर्ष के थे।

श्री माथुर आपातकाल के दौरान जेल भी गए और 1975 में संघ के प्रचारक बने। उन्होंने बालासाहेब देवरस, के.एस. सुदर्शन, बाबासाहेब नातू और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे वरिष्ठ प्रचारकों के साथ काम किया। उन्होंने एक प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में काम किया और 1994 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। वे हरियाणा में राज्य भाजपा इकाई के संगठन महामंत्री रहे।

उन्होंने श्री नर्मदे हर सेवा न्यास की स्थापना के लिए अपनी पुश्तैनी संपत्ति दान कर दी। यह ट्रस्ट वन आवास क्षेत्रों में समाज सेवा के विभिन्न प्रोजेक्ट चला रहा है। उनका अंतिम संस्कार 15 दिसंबर को सुभाष नगर विश्राम घाट पर हुआ। श्री माथुर के निधन पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा सहित विभिन्न भाजपा नेताओं ने शोक व्यक्त किया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व सह महामंत्री (संगठन) श्री भगवत शरण माथुर के निधन की खबर दुःखद है। उन्होंने संगठन

में अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों का समर्पित भाव से निर्वहन करते हुए पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जाना भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ■

उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरबंस कपूर का निधन

उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरबंस कपूर का 13 दिसंबर को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विधायी कार्य में कुशल श्री कपूर का जन्म 7 जनवरी, 1946 को हुआ था। वह देहरादून कैंट सीट से विधायक थे। श्री कपूर ने उत्तराखंड विधान सभा के अध्यक्ष, मंत्री आदि के तौर पर विभिन्न भूमिकाओं का सम्यक् निर्वहन किया।

श्री हरबंस कपूर अविभाजित उत्तर प्रदेश में शहरी विकास मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। वर्ष 2007 में श्री कपूर उत्तराखंड विधान सभा के अध्यक्ष बने। श्री कपूर आठ बार विधानसभा के सदस्य रहे, जिसमें वह चार बार उत्तर प्रदेश विधान सभा और चार बार उत्तराखंड विधान सभा के सदस्य रहे। वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य थे।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में उन्होंने देहरादून शहर की सीट जीती और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वे देहरादून खास सीट से विधायक रहे। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित देहरादून कैंट सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

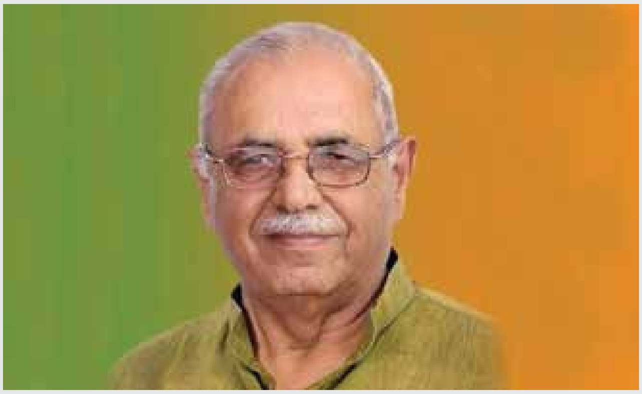

राजनीति में श्री कपूर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे समाज के सभी वर्गों में बहुत लोकप्रिय थे और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने हमेशा लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी और उनका राजनीतिक जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। ■

हमारा शहर स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए: नरेन्द्र मोदी

नदियों को शहरी जीवन के केंद्र में वापस लाया जाना चाहिए। इससे शहरों को एक नया जीवन मिलेगा

गत 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्राचीन शहर वाराणसी में हाल के घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने अपने वक्तव्य को दोहराया कि काशी का विकास पूरे देश का रोडमैप हो सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर ही हैं, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता की भी उतनी ही अहमियत है। उन्होंने कहा कि ये शहर हमें विरासत और स्थानीय कौशल को संरक्षित करना सिखा सकते हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि मौजूदा संरचनाओं को नष्ट करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि कायाकल्प और संरक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। इसे आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।

श्री मोदी ने स्वच्छता के लिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया और उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि क्या उन शहरों को मान्यता देने के लिए नई श्रेणियां हो सकती हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों के साथ-साथ स्वच्छता हासिल करने के लिए सबसे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता के साथ-साथ शहरों के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने महापौर से इस संबंध में अपने शहरों में वार्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने को कहा।

श्री मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि महापौरों को समय निकालकर शहरों का जन्मदिन मनाना चाहिए। नदियों वाले शहरों को नदी उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने नदियों की महिमा को फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि लोग उन पर गर्व करें और उन्हें स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि नदियों को शहरी जीवन के केंद्र में वापस लाया जाना चाहिए। इससे आपके शहरों को एक नया जीवन मिलेगा।

उन्होंने महापौरों से सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे के खिलाफ अभियान को फिर से शुरू करने को कहा। श्री मोदी ने महापौरों से कचरे से धन बनाने के तरीके तलाशने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारा शहर स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।

श्री मोदी ने महापौरों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके शहरों की स्ट्रीट लाइटों और घरों में एलईडी बल्बों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने इसे एक मिशन मोड में लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा मौजूदा योजनाओं को नए उपयोग के लिए इस्तेमाल करने और उन्हें आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए।

श्री मोदी ने 'एक जिला एक उत्पाद' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए महापौरों से शहर में किसी विशिष्ट उत्पाद या स्थान द्वारा प्रचारित अपने शहरों की एक विशिष्ट पहचान के लिए जोर देने को कहा। प्रधानमंत्री ने उनसे शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जनहितैषी सोच विकसित करने को भी कहा। श्री मोदी ने कहा कि हमें सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है।

श्री मोदी ने हमारे विकास मॉडल में एमएसएमई को मजबूत करने की आवश्यकता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वाले हमारी अपनी ही यात्रा के अंग है, इनकी मुसीबतों को हम हर पल देखेंगे। उनके लिए हम 'पीएम स्वनिधि योजना' लाए हैं। यह योजना बहुत ही उत्तम है। आप अपने नगर में उनकी लिस्ट बनाइए और उनको मोबाइल फोन से लेन-देन सिखा दीजिए। इससे बेहतर शर्तों पर बैंक वित्त की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि महामारी ने स्ट्रीट वेंडर्स के महत्व को दिखाया है।

श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल अहमदाबाद के महापौर थे और देश उन्हें आज भी याद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महापौर का पद एक सार्थक राजनीतिक करियर के लिए एक ठोस आधार हो सकता है, जहां आप इस देश के लोगों की सेवा कर सकते हैं। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, 8 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री 'अयोध्या आरती' में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'भव्य काशी-दिव्य काशी' कार्यक्रम में शामिल होने के दो दिन बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के आठ मुख्यमंत्रियों और पांच उप मुख्यमंत्रियों के एक दल ने 15 दिसंबर, 2021 को अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान इस दल के सदस्यों ने हनुमानगढ़ी मंदिर और राम जन्मभूमि में पूजा-अर्चना की और सरयू के तट पर 'आरती' में शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास द्वारा राम लला मंदिर में एक विशेष पूजा की गई, वहीं अयोध्या के महंत श्री शशिकांत दास द्वारा सरयू आरती की गई।

अयोध्या में उपस्थित मुख्यमंत्रियों में मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के श्री बिप्लब देब, गोवा के डॉ. प्रमोद सावंत, हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर, असम के श्री हेमंत बिस्वा सरमा, गुजरात के श्री भूपेंद्रभाई पटेल, अरुणाचल प्रदेश के श्री प्रेमा खांडू और मणिपुर के श्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह शामिल थे। उप मुख्यमंत्रियों में नागालैंड के श्री यानथुंगो पैटन, अरुणाचल प्रदेश के श्री चोना मीन, बिहार के श्री तारकिशोर और श्रीमती रेणु देवी और गोवा के श्री चंद्रकांत बाबू कावलेकर शामिल थे।

श्री नड्डा को इस अवसर पर भव्य राम मंदिर का एक मॉडल दिया गया, वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सभी मुख्यमंत्रियों ने काशी धाम गलियारे के उद्घाटन के दौरान राम लला के 'दर्शन' करने की इच्छा व्यक्त की। हम भी मंदिर निर्माण की समीक्षा करना चाहते थे। काशी आने के बाद सभी मुख्यमंत्री आपस में समय-समय पर मिलते रहे। यह सभी राम लला के मंदिर में पूजा करना चाहते थे।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मैं मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद राम जन्मभूमि का दौरा कर स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं," वहीं असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "हिंदू धर्म कोई एजेंडा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। भगवान राम के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। ■

केरल भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रंजीत श्रीनिवासन की कट्टरपंथी तत्वों ने हत्या की

भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री श्री रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर को उनकी मां और पत्नी की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। इस हत्या में शामिल 12 अपराधियों का गिरोह मोटर साईकिल पर सवार होकर श्री श्रीनिवासन के अलाप्पुझा शहर स्थित घर पहुंचा था। भाजपा नेता श्री रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में एसडीपीआई के 11 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। एसडीपीआई के चार कार्यकर्ताओं को एंबुलेंस से पकड़ा गया। एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का राजनीतिक संगठन है। पुलिस का कहना है कि हत्या सुनियोजित थी। पुलिस को श्री रंजीत के घर की ओर जा रही छह बाइकों पर सवार 12 लोगों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। जिसमें ये लोग हमले के बाद लौटते हुए दिखायी दे रहे हैं। जब श्री रंजीत मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कानून का राज नहीं है। उन्होंने प्रदेश ओबीसी मोर्चा के नेता श्री रंजीत श्रीनिवासन की हत्या की निंदा की। श्री नड्डा ने कहा, "ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री अधिवक्ता श्री रंजीत श्रीनिवासन की 'कट्टरपंथी तत्वों' द्वारा निर्मम हत्या निंदनीय है। इस तरह की कायराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में केरल में कानून का राज नहीं है। वे अपनी क्रूरता से हमें डरा नहीं सकते।

केंद्रीय मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता श्री रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के पीछे एक इस्लामिक आतंकवादी समूह है, जिनकी अज्ञात लोगों ने उनके घर पर हत्या कर दी थी। केंद्रीय मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने मांग की कि केरल सरकार अलाप्पुझा जिले में भाजपा के नेता की हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ■

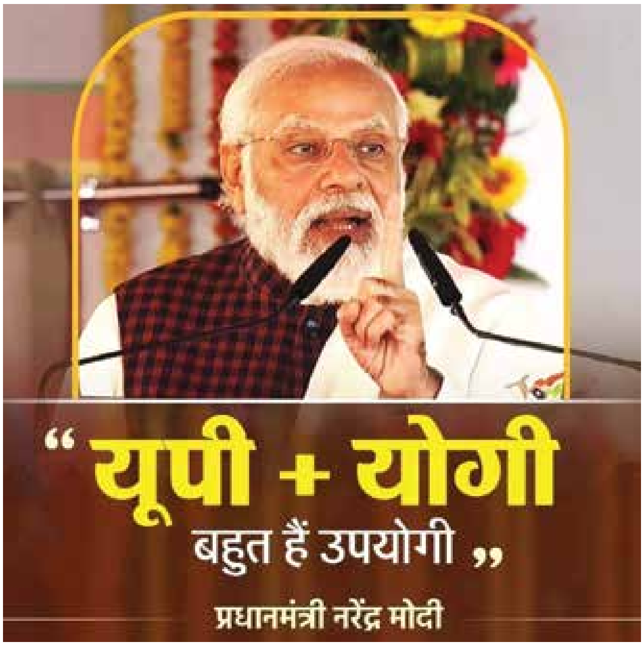

गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा

गत 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री श्री बी.एल. वर्मा व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने काकोरी कांड के क्रांतिकारियों, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रौशन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। श्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम के कवियों, दामोदर स्वरूप 'विद्रोही', राज बहादुर विकल और अग्निवेश शुक्ल को स्थानीय बोली में श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रौशन सिंह का बलिदान दिवस है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है।

श्री मोदी ने कहा कि मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत हैं। मां गंगा सारे सुख देती हैं और सारी पीड़ा हर लेती हैं। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस-वे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। एक्सप्रेस-वे, नए हवाई अड्डों और रेल-मार्गों के नेटवर्क का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह राज्य के लिए पांच वरदानों का स्रोत होगा। पहला वरदान— लोगों के समय की बचत। दूसरा वरदान— लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी। तीसरा वरदान— यूपी के संसाधनों का सही उपयोग। चौथा वरदान— यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि। पांचवा वरदान— यूपी में चौतरफा समृद्धि।

श्री मोदी ने पांच साल पहले की स्थिति की ओर लोगों का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ इलाकों को छोड़कर, अन्य शहरों और गांव-देहात में बिजली ढूढ़े नहीं मिलती थी। डबल इंजन की सरकार ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 80 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, बल्कि हर जिले को पहले से कई गुना ज्यादा बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक गरीब लोगों को पक्के मकान मिले हैं और यह अभियान शेष सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए जारी रहेगा। शाहजहांपुर में भी 50 हजार पक्के मकान बने।

एक नजर में गंगा एक्सप्रेस-वे

कुल 594 किलोमीटर की लंबाई वाला छह लेन का गंगा एक्सप्रेस-वे 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के निकट से शुरू होकर यह एक्सप्रेस-वे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव के निकट तक जाएगा। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। काम पूरा होने पर यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बन जाएगा। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। इस एक्सप्रेस-वे के किनारे पर एक औद्योगिक गलियारा भी बनाने का प्रस्ताव है।

श्री मोदी ने देश की विरासत के साथ-साथ देश के विकास के काम से भी ईर्ष्या करने वाली मानसिकता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन गरीब और आम लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को काशी में 'बाबा विश्वनाथ' का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगाजी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं।

उन्होंने राज्य में खराब कानून व्यवस्था की स्थिति की याद दिलाई जो हाल के दिनों में बदलकर बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री ने U.P.Y.O.G.I – यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी– का सूत्र दिया। ■

'प्राकृतिक खेती से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा, वो हैं देश के 80 प्रतिशत किसान'

कृषि से जुड़े हमारे प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की ज़रूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी ज़रूरत है। इस दिशा में हमें नए सिरे से शोध करने होंगे, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में ढालना होगा

गत 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राकृतिक खेती विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, गुजरात के राज्यपाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित थे।

किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आज़ादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। श्री मोदी ने कहा कि बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाज़ार तक, किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का डेढ़ गुणा एमएसपी तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने इस आयोजन से जुड़े सभी किसानों को बधाई दी।

श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है, उतना ही 'बैक टू बेसिक' की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना! इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है? हम जितना जड़ों को सींचते हैं, उतना ही पौधे का विकास होता है।

उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े हमारे इस प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की ज़रूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी ज़रूरत है। इस दिशा में हमें नए सिरे से शोध करने होंगे, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में ढालना होगा।

श्री मोदी ने कहा कि जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है, तो वो ईंट का रूप ले लेती है। लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारे यहां परंपरा सी पड़ गई है।

उन्होंने कहा कि एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी नहीं होगी, जबकि सच्चाई इसके बिलकुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे, लेकिन फसल अच्छी होती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा, वो हैं देश के 80 प्रतिशत किसान। वो छोटे किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च, केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। श्री मोदी ने कहा कि अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी।

उन्होंने कहा कि मैं आज देश के हर राज्य से, हर राज्य सरकार से, ये आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने के लिए आगे आएं। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव ज़रूर प्राकृतिक खेती से जुड़े, ये प्रयास हम कर सकते हैं।

श्री मोदी ने याद करते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ (एलआईएफई) को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया था। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा, "आइये, आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें।"

गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर, 2021 तक आयोजित किया गया। इसमें आईसीएआर के केंद्रीय संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और एटीएमए (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी) नेटवर्क के माध्यम से जुड़े किसानों के अलावा 5000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। ■

मोदी सरकार के सुशासन से बदल रही पूर्वोत्तर की तस्वीर

राजू बिष्ट

भारत में पूर्वोत्तर के आठों राज्यों का गौरवशाली इतिहास है। यहां की विविध जातीय परम्परा, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत अतुलनीय है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य, मानव पूंजी, प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और प्राकृतिक सुन्दरता से समृद्ध हैं। यही वजह है कि पूर्वोत्तर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन का केंद्र बनने की भरपूर संभावना है। प्रधानमंत्री मोदीजी खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि पूर्वोत्तर में देश के विकास का इंजन बनाने की क्षमता है। सुखद है कि अब मोदी सरकार में तेजी से पूर्वोत्तर की सूरत संवर रही है। पूर्वोत्तर के राज्य सतत विकास की ओर अग्रसर हैं।

हालांकि, स्वतंत्रता के बाद लगभग छह दशकों तक संभावनाओं से भरे इस क्षेत्र को दरकिनार कर दिया गया था। गड़बड़ी और अशांति का हवाला देते हुए कांग्रेस सरकारों ने इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने और सुलझाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। दिल्ली में बैठी उदासीन सरकारों ने हमेशा उत्तर-पूर्व से संबंधित सभी मुद्दों को दबाने की कोशिश की, जिसके कारण पूर्वोत्तर के लोगों को व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशांति और पिछड़ेपन की स्थिति का सामना करना पड़ा। इससे हमारे युवाओं का सिस्टम से मोहभंग हो गया और कुछ ने अपनी आवाज सुनाने के लिए हथियार उठाने का सहारा भी लिया।

मैं, 80 और 90 के दशक के उथल-पुथल भरे दशकों के दौरान मणिपुर के एक छोटे से गांव चार हजारे में पला-बढ़ा, जब उग्रवाद, हिंसा और राजनीतिक अशांति अपने चरम पर थी। विकास एक दूर का सपना लग रहा था, लोगों के पास एक्सपोजर के रास्ते नहीं थे और शायद मैं भाग्यशाली था कि मुझे अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल गया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालने के साथ ही यह सब बदल गया। वह भारत को बदलने की दृष्टि के साथ आए और उत्तर-पूर्वी भारत को फिर से भारत की विकास प्राथमिकताओं में सबसे आगे रखा गया।

नॉर्थ ईस्ट पर खास फोकस

सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदीजी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को हर पखवाड़े एक पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत रूप से आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदीजी, पिछले वर्षों में कई बार पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरों ने नीति निर्माताओं और लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के बीच समझ की खाई को पाटने में मदद की।

> बेहतर हवाई संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, पेयजल, आवास सुनिश्चित करने और युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 68,020 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है

प्रधानमंत्री मोदीजी के प्रयासों ने शासन और नीतियों के मामले में दिल्ली को उत्तर-पूर्व के लोगों के बहुत करीब लाया है। आज पूर्वोत्तर के लोग शेष भारत से भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।

परिवर्तन का साक्षी

2014 के बाद से उत्तर पूर्व भारत में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदीजी की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदलने की पहल को सराहना मिल रही है। सड़क के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार बड़ा निवेश कर रही है। पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के तहत 80,007 करोड़ रुपये और भारतमाला परियोजना के तहत अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये दिए गए। इसी तरह, भारतीय रेलवे इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क में सुधार के लिए 74,485 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है और पूर्वोत्तर में हर राज्य की राजधानी को राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जोड़ेगा।

असम में भारत के सबसे लंबे रेलमार्ग बोगीबील ब्रिज का निर्माण पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार के फोकस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अटलजी द्वारा वर्ष 2002 में उद्घाटन किया गया, जबकि मोदी सरकार में वर्ष 2018 में

यानी करीब डेढ़ दशक से अधिक समय बाद इस पुल को पूरा किया गया। कांग्रेस ने दो कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बावजूद इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए कोई कवायद नहीं की।

बेहतर हवाई संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, पेयजल, आवास सुनिश्चित करने और युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 68,020 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। अकेले शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए 8500 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। उच्चतम स्तर पर सरकार के फोकस ने पूरे उत्तर-पूर्व में बुनियादी ढांचा सेवाओं को नाटकीय रूप से बदल दिया है। बेहतर बुनियादी ढांचा युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद कर रहा है। यह क्षेत्र, जिसे सुविधाओं की कमी के कारण पर्याप्त 'ब्रेन ड्रेन' का सामना करना पड़ा, आखिरकार अपने युवाओं को वही रहने और अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए मनाने में सक्षम हुआ है। लेकिन यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है।

> हमारी दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्र में भी बहुत उत्साह और आशा है, जहां लोग मजबूती से प्रधानमंत्री मोदीजी के साथ खड़े हैं और लंबे समय से लंबित स्थायी राजनीतिक समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं

निर्णायक शासन

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व की एक पहचान 'निर्णायक शासन' है। फैसले त्वरित होते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति लाने के लिए स्पष्टता के साथ निर्णायक रूप से काम किया है। 2015 में हमारी सरकार ने 80 दौर की बातचीत के बाद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-IM) के साथ ऐतिहासिक 'नागा शांति समझौते' पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने देश में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संघर्ष और सशस्त्र विद्रोह में से एक को समाप्त कर दिया। हाल ही में एनएससीएन (के) के निकी सुमी के नेतृत्व वाले खापलांग गुट के साथ एक और युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, सरकार शांति की दिशा में काम कर रही है।

सभी नागा राष्ट्रवादी राजनीतिक समूहों (एनएनपीजी) के साथ बातचीत की पहल हुई। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) और अन्य हितधारकों के गुटों के साथ 2020 'बोडो शांति समझौता' के कारण निचले असम क्षेत्र में शांति आई है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के रूप में रहने वाले ब्रू-रियांग लोगों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में हल किया गया है।

हाल ही में 'कार्बी-आंगलोंग शांति समझौते' ने असम के कार्बी-आंगलोंग जिले में तीन दशक पुराने राजनीतिक संघर्ष को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदीजी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार एक शांतिपूर्ण जीवन शैली सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। जहां सभी जाति, भाषा और संस्कृति के सभी लोग शांति और सद्भाव में एक साथ रह सकें और फल-फूल सकें।

आशावादी भविष्य

यह मोदीजी में लोगों की अटूट आस्था और विश्वास था, जिसने मणिपुर के एक सुदूर गांव के मुझ जैसे एक गोरखा युवा को पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित दार्जिलिंग लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। जैसाकि उत्तर-पूर्वी भारत से संबंधित अन्य विवादास्पद मुद्दों को हल किया गया है, हमारी दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्र में भी बहुत उत्साह और आशा है, जहां लोग मजबूती से प्रधानमंत्री मोदीजी के साथ खड़े हैं और लंबे समय से लंबित स्थायी राजनीतिक समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे हमारे क्षेत्र का सामना कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दशकों के संघर्ष के बाद दार्जिलिंग क्षेत्र के लोग भी सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम होंगे। ■

(लेखक दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

प्रधानमंत्री मोदी को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार
भारत के लिए गौरव का पल

राम प्रसाद त्रिपाठी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' से सम्मानित किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय के दौरान भारत ने भूटान को बिना शर्त समर्थन दिया, इसलिए भूटान प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "महामहिम द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' के लिए महामहिम नरेन्द्र मोदीजी का नाम उच्चारण सुनते हुए बहुत खुशी हुई।'' इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान के राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत हमेशा भूटान को अपने सबसे करीबी दोस्तों और पड़ोसियों में से एक के रूप में संजोकर रखना चाहता है और उसकी विकास यात्रा को आगे भी सहयोग देता रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने सतत विकास के अपने अद्वितीय मॉडल और जीवन जीने के गहन आध्यात्मिक तरीके के लिए भूटान की प्रशंसा की और भूटान को एक विशिष्ट पहचान देने और भारत के साथ उसकी मित्रता और साझेदारी को बनाये रखने के लिए वहां के अब तक के राजाओं को धन्यवाद दिया।

हालांकि, 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद से श्री मोदी को प्रदान किया जाने वाला यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सम्मान नहीं है। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रों की मदद करने के लिए कई अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी दिए गए हैं।

भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही अपने करिश्माई नेतृत्व, दूरदृष्टि, मिशन और कौशल से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित किया है। उनकी रचनात्मक सोच, अनुकरणीय नेतृत्व और वैश्विक समुदाय के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सहित दुनिया के कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न केवल विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए, बल्कि अपने विशिष्ट नेतृत्व और प्रयासों से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और फाउंडेशनों को भी प्रभावित किया। यही कारण है कि पूरी दुनिया श्री मोदी के हर कदम और घटनाक्रम पर

प्रधानमंत्री श्री मोदी को सम्मान देने वाले देश

1. **भूटानः** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 2021 में भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' से सम्मानित किया।
2. **संयुक्त राज्य अमेरिकाः** प्रधानमंत्री श्री मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित 'लीजन ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया, जो 2020 में अमेरिकी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है।
3. **रूसः** प्रधानमंत्री श्री मोदी को 2019 में 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू' से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 1698 में स्थापित किया गया था। रूसी संघ का यह सर्वोच्च पुरस्कार श्री मोदी को भारत-रूस संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अनुकरणीय भूमिका के लिए दिया गया था। श्री नरेन्द्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं।
4. **मालदीवः** विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए मालदीव का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड 'रूल ऑफ निशान इजुद्दीन' से साल 2019 में प्रधानमंत्री श्री मोदी को सम्मानित किया गया।
5. **अफगानिस्तानः** प्रधानमंत्री श्री मोदी को 2016 में 'अमीर अमानुल्ला खान अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया था। यह अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
6. **सऊदी अरबः** खाड़ी देश ने 2016 में प्रधानमंत्री श्री मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद' से सम्मानित किया।
7. **फिलिस्तीनः** भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को 2018 में 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन' पुरस्कार मिला।
8. **संयुक्त अरब अमीरातः** संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' पुरस्कार है जो 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रदान किया गया था। यह केवल देश के सर्वोच्च गणमान्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
9. **बहरीनः** प्रधानमंत्री श्री मोदी को 2019 में बहरीन के शीर्ष पुरस्कार 'किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां' से सम्मानित किया गया।

ध्यान देती है और वैश्विक स्तर पर उनके परोपकारी कार्यों का सम्मान करती है।

विभिन्न संगठनों/फाउंडेशनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार

- **सियोल शांति पुरस्कार:** सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को मानव जाति के बीच सद्भाव, राष्ट्रों के बीच सुलह और विश्व शांति स्थापित करने को लेकर उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2018 में सम्मानित किया गया।
- **चैंपियंस ऑफ द अर्थ:** 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी को दिया गया यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएन पर्यावरण) ने 2005 में 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' की स्थापना की। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड निजी/सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्यावरण को लेकर उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
- **फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल एवार्ड:** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दिया जाने वाला पहला पुरस्कार है-2019।
- **ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार:** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान-2019 के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 'ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड' से सम्मानित किया गया है।
- **वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशीप पुरस्कार:** कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स सीईआरए द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित किया गया (यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण को लेकर नेतृत्व की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है) -2021।

उपरोक्त सम्मानों और पुरस्कारों के अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कई अन्य वैश्विक मान्यताएं प्रदान की गई हैं जिनमें शामिल हैं:

1. मार्च, 2012 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को टाइम पत्रिका के एशियाई संस्करण के कवर पर स्थान मिला।
2. श्री मोदी को 2014 और 2016 में 'पर्सन ऑफ द ईयर' के लिए 'टाइम मैगजीन रीडर्स पोल' का विजेता भी घोषित किया गया था।
3. 2015 में फॉर्च्यून पत्रिका की 'विश्व के महानतम नेताओं' की पहली वार्षिक सूची में प्रधानमंत्री श्री मोदी को 5वां स्थान दिया गया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिर बढ़ाया भारत का मान

भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान

'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो'

से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को किया सम्मानित।

4. 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ट्विटर पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राष्ट्राध्यक्ष बनें।
5. फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें 2014 में दुनिया में 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का स्थान दिया।
6. 2016 में लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में प्रधानमंत्री श्री मोदी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मिले इन पुरस्कारों और वैश्विक सम्मानों ने न केवल उन्हें एक सच्चे वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है, बल्कि इससे हमारे क्षेत्र और विश्व स्तर पर हमारे राष्ट्र की पहचान भी बढ़ी है। उनके करिश्माई नेतृत्व में एक नए और आत्मनिर्भर भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांतों के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक समृद्धि के लिए अथक प्रयास किए है और महामारी के कठिन समय में भी वैश्विक समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। भारत निश्चित रूप से हर जरूरतमंद देश का मित्र साबित हुआ है। यदि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के योगदान को पहचान रही है, तो उन्हें दिए गए सम्मानों ने न केवल उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को ऊंचा किया है, बल्कि देश और इसकी 130 करोड़ से अधिक की आबादी को भी एक नयी पहचान और सम्मान दिया है। ■

मोदी के नेतृत्व में भारत पुराने दोस्त को खोए बिना नए दोस्त बना रहा है

विकास आनंद

20 दिसंबर, 2021 को रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पुतिन की हाल की भारत यात्रा के दौरान चर्चा किए गए कुछ मुद्दों पर बात की। टेलीफोनिक एक्सचेंज में इन मुद्दों के कार्यन्वन से सम्बंधित पहलुओं पर दोनों नेता अवगत हुए, जिसमें रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसर, उर्वरकों की आपूर्ति में सहयोग और रूसी सुदूर पूर्व के साथ भारत के जुड़ाव को बढ़ाना शामिल है। दोनों नेताओं ने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के तहत शामिल सभी पहलुओं पर नियमित संपर्क में रहने और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ परामर्श और समन्वय को और गहरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की।

दिसंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति पुतिन ने 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत और रूस ने 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, व्यापार, सैन्य प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक रूसी एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की डिलीवरी के लिए मोदी सरकार की मंजूरी थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के साथ इस समझौते को मंजूरी दी। क्योंकि, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, सीएटीएसए) के तहत भारत अमरीकी सम्बन्ध प्रभावित हो सकते थे. सीएटीएसए को अमरीका ने 2017 में संघीय कानून बनाया। इस कानून के तहत कोई भी देश जो रूस के रक्षा क्षेत्र के साथ 'महत्वपूर्ण लेनदेन' करता है, उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए पहली बार किसी भारतीय नेतृत्व ने वाशिंगटन और क्रेमलिन के साथ भारत के संबंधों को संतुलित करने की क्षमता दिखाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने कुटनीतिक कौशल के बद्दौलत सीएटीएसए के तहत भारत-अमेरिकी आर्थिक-राजनीतिक सम्बन्ध में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया। इससे पहले, भारतीय नेतृत्व को दोनों शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करना मुश्किल पड़ता था। आम तौर पर यह देखा गया कि एक शक्ति के साथ भारत के बढ़ते सम्बन्ध की परिणति दूसरे के साथ संबंधों में गिरावट के रूप में होती थी । अतीत में, पश्चिम के साथ रूस के संबंधों की जटिलता ने भारत के भू-रणनीतिक और सुरक्षा हितों को प्रभावित किया। श्री मोदी के उपयुक्त राजनयिक कौशल ने लम्बे समय से चले आ रहे इस तरह के गतिरोध को दूर किया और भारत को अपनी सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन में सक्षम बनाया। दूसरे शब्दों में, मोदी के नेतृत्व में भारत पुराने दोस्त को खोए बिना नए दोस्त बना रहा है। भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञ एस-400 मिसाइल सौदे को भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से अहम सौदा मानते हैं। यह दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली है। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के साथ देश की सीमा के साथ पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन को तैनात करना शुरू कर दिया है। वायु रक्षा प्रणाली भारतीय सेना को दक्षिण एशिया में बढ़त दिलाएगी, क्योंकि वे चीन और पाकिस्तान दोनों के आक्रमणकारी विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने में सक्षम होंगे। यह 400 किमी की दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस रक्षा प्रणाली को तैनात करने में सबसे कम समय लगता है। यह पांच मिनट में लॉन्च के लिए तैयार हो सकता है।

भारतीय समाचार पत्रिका 'द वीक' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली चार अलग-अलग मिसाइलों से लैस है जो दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWACS विमानों को 400 किमी, 250 किमी, मध्यम दूरी की दूरी 120 किमी पर और न्यूनतम 40 किमी की दूरी पर मार सकती है। S-400 एक साथ 80 लक्ष्यों का सामना कर सकती है और एक ही समय में 160 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। S-400, 600 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है और 400 किलोमीटर दूर से उसे नष्ट कर सकती है।

थिंक टैंक ओआरएफ (ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन) ने क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में सौदे को 'महत्वपूर्ण' बताया है। चीन-भारत सीमा के साथ कई स्थानों पर पिछले साल 2020 के सशस्त्र गतिरोध और झड़पों के मद्देनजर, और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन द्वारा अपनी S-400 रक्षा प्रणाली के साथ अपने सैन्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन को देखते हुए भारत के उन्नत रक्षा तकनीक के तैनाती से जैसे कि एस-400; भारतीय बलों को किसी भी हवाई खतरे से निपटने में फायदा मिलेगा। ■

डिजिटल इंडिया लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला रहा है

राजीव कुमार

डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक ऐसी अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य सभी छोटे और बड़े सरकारी विभागों को डिजिटल रूप देकर उनकी गति को तीव्र से तीव्रतम कर देना है। इससे लाभ यह होगा कि बिना कागज के प्रयोग के सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक निर्वाध रूप से पहुंच सकेंगी व अविलंब कार्य को पूरा किया जा सकेगा। भारत के हर नागरिक को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए सरकार ने यह बेहद महत्वपूर्ण और सही कदम उठाया है जो आने वाले भविष्य में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत सुधार तो होगा ही साथ में देश में नई टेक्नोलॉजी का भी विकास होगा।

डिजिटल इंडिया योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह कि ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। देखा जाए तो डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं : पहला, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और तीसरा, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

एक कार्यक्रम के तहत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान आरंभ किया था जिसका आज पूरे भारत में विस्तार देखा जा सकता है।

देश को डिजिटल रूप से विकसित करने और देश के आईटी संस्थान में सुधार करने के लिए डिजिटल इंडिया महत्वपूर्ण पहल है। डिजिटल इंडिया अभियान की विभिन्न योजनाओं जैसे डिजिटल लॉकर, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-साइन आदि को शुरु करके इस कार्यक्रम का अनावरण किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल ताकत को समझना समय की मांग है और अगर यह नहीं किया गया तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश 'एम-गवर्नेंस' में बदलने वाला है मतलब 'मोबाइल-गवर्नेंस' से है।

डिजिटल इंडिया भारत का सद्-संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत की साधना है। सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच सारी दूरियों को समाप्त करना समय की मांग है। डिजिटल इंडिया ने ये कैसे संभव किया है इसका शानदार उदाहरण डिजीलॉकर (Digi Locker) है, भारत सरकार के स्रोत के मुताबिक 30 नवंबर, 2021 तक 8.80 करोड़ लोग डिजीलॉकर के सक्रिय प्रयोगकर्ता हैं वहीं

1.78 लाख लाख ग्राम पंचायतें आप्टिकल फाइबर से जुड़ गईं हैं और 59000 से अधिक स्टाट्र्सअप कार्यरत हैं, जो हमारे स्वप्न को एक नया आयाम दे रहे हैं।

बिजली बिल, पानी बिल, इनकम टैक्स भरना एकदम आसान और तेज डिजिटल इंडिया से ही संभव हुआ है। गरीबों को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को आसान किया है, एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर दवाई तक में डिजिटल इंडिया में अहम भूमिका रही है। सही मायने में देखा जाए तो डिजिटल इंडिया से न्यू इंडिया का सपना मोदी जी ने जो देखा था वो अब साकार हो रहा है। डिजिटल लेन-देन में 2016 से 2021 तक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है : UPI (यूपीआई) पर लेन-देन का मूल्य (रूपये बिलियन) में देखा जाए तो 2016 में कुल 69 बिलियन था जो 2020-21 में बढ़कर 41,306 बिलियन हो गया। वहीं POS (पीओएस) पर RUPAY कार्ड के उपयोग का मूल्य (रूपये बिलियन) में 2016-17 में 289 बिलियन से बढ़कर 2020-21 में 1,169 बिलियन हो गया।

कोविड काल में हमें डिजिटल इंडिया ने हमारे सारे कार्यों को एकदम से सरल और सुलभ बना दिया था। डिजिटल इंडिया मतलब

भाजपा का लक्ष्य विकास और 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाना है: नरेन्द्र मोदी

14 दिसंबर, 2021 को वाराणसी में मुख्यमंत्री परिषद् की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्री एवं पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने भाग लिया।

यह बैठक नागरिकों के जीवन को बेहतर करने वाली सुशासन प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित थी। मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियां दीं और अपने राज्यों की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को बैठक में रखा। इस दौरान उन्होंने राज्यों में शुरू की गई नवीन शासन प्रथाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान प्रस्तुत की गई कुछ प्रमुख प्रथाओं में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा परियोजनाएं, पारिवारिक पहचान पत्र जारी करना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए ग्रामीण आजीविका के कार्यक्रम शामिल थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी टिप्पणी में शासन के विभिन्न आयामों से संबंधित कई बिंदु रखे। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली प्रत्येक सरकार से शासन के किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने सरकारों से 'ईज ऑफ लिविंग' को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से पुराने कानूनों को हटाने और अनुपालन बोझ को कम करने का आग्रह किया।

शासन में प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने अंतिम मील तक वितरण सुनिश्चित करने, कार्य में गति और पारदर्शिता लाने के लिए डेटा आधारित प्रणाली के उपयोग का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यों से आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनने के लिए 'एक जिला, एक उत्पाद' पर काम करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने हर सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में युवा विकास और महिला सशक्तिकरण के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

अपने उद्घाटन भाषण में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री की सफलता की सराहना की, जिन्होंने सरकार के प्रमुख के रूप में दो दशक पूरे किए है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और सुशासन पर्याय बन गए हैं और भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने प्रदर्शन के आधार पर जनादेश चाहती है।

बैठक के अंत में पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा ने सभी मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों के साथ वाराणसी विकास प्राधिकरण की गोवर्धन परियोजना, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल और सारनाथ का भी प्रवास किया। ■

एकदम पारदर्शी व्यवस्था। डिजिटल यानी तेजी से लाभ देने वाली एक ऐसी प्रणाली जो मानव जीवन को एकदम सुगम्य बना देती है। ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, भारत की दर्जनों डिजिटल कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होंगी।

इस तरह डिजिटलीकरण से आगे चलकर डिजिटल लेन-देन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा सकेगी। 24 नवंबर, 2021 तक के भारत सरकार के स्रोतों को देखा जाए तो गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सार्वजनिक खरीद में एक अद्भुत क्रांति आ रही है: पोर्टल के माध्यम कुल लेन-देन 1.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक, विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत 31.71 लाख से भी अधिक और उत्पाद उपलब्धता 63.46 लाख से अधिक हो चुका है।

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिम्सटेक देशों के बीच कह चुके हैं कि यह सदी डिजिटल क्रांति और नए युग के नवाचारों की सदी है। यह एशिया की सदी भी है इसलिए यह हमारे समय की मांग है कि भविष्य की प्रौद्योगिकी और उद्यमी इसी क्षेत्र से उभरें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'द सिडनी डायलॉग' में भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय पर कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र में निहित हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल तकनीक से लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है। यह संप्रभुता, शासन, नैतिकता, क़ानून, अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है।

श्री मोदी ने कहा, ''प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बन गई है, ये भविष्य की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी है। प्रौद्योगिकी और डेटा नए हथियार बन रहे हैं।'' ■

'गोवा के लोगों ने मुक्ति और स्वराज के आंदोलनों को थमने नहीं दिया'

भारत एक ऐसा भाव है, जहां राष्ट्र 'स्व' से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जहां एक ही मंत्र होता है— राष्ट्र प्रथम; जहां एक ही संकल्प होता है— 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 दिसंबर को गोवा में आयोजित गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भाग लिया। श्री मोदी ने समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और 'ऑपरेशन विजय' से जुड़े सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें प्रमुख हैं— पुनर्निर्मित फोर्ट अगुआड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और डाबोलिम-नावेलिम, मडगांव में गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन आदि। उन्होंने गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च की आधारशिला भी रखी।

सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को, प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है और आज सभी का, गोवा के लोगों का ये जोश, गोवा की हवाओं में मुक्ति के गौरव को और बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे आज़ाद मैदान में शहीद मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य भी मिला। शहीदों को नमन करने के बाद मैं मीरामर में सेल परेड और फ़्लाइ पास्ट का साक्षी भी बना। उन्होंने यहां आकर ऑपरेशन विजय के वीरों को, सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को देश की ओर से सम्मानित करने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

श्री मोदी ने कहा कि गोवा एक ऐसे समय पुर्तगालियों के अधीन हुआ था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग भाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे। श्री मोदी ने कहा कि समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच सदियों की दूरी के बाद भी न तो गोवा अपनी भारतीयता को भूला और न ही भारत अपने गोवा को भूला। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और सशक्त ही हुआ है। गोवा के लोगों ने मुक्ति और स्वराज के आंदोलनों को थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जलाए रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है। भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा भाव है, जहां राष्ट्र 'स्व' से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जहां एक ही मंत्र होता है— राष्ट्र प्रथम; जहां एक ही संकल्प होता है— एक भारत, श्रेष्ठ भारत।

श्री मोदी ने इस राज्य को खुले में शौच मुक्त बनाने, टीकाकरण, 'हर घर जल', जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण और लोगों की जिंदगी को और भी अधिक आसान बनाने के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं की शानदार प्रगति में गोवा का उदाहरण दिया। उन्होंने 'स्वयंपूर्ण गोवा अभियान' के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य के शासन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न ठोस कदमों के बारे में भी बताया।

श्री मोदी ने दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गोवा की इन उपलब्धियों को, इस नई पहचान को जब मैं मजबूत होते देखता हूं तो मुझे मेरे अभिन्न साथी मनोहर पर्रिकर जी की भी याद आती है। उन्होंने न केवल गोवा को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि गोवा की क्षमता का भी विस्तार किया। आखिरी सांस तक कोई कैसे अपने राज्य, अपने लोगों के लिए लगा रह सकता है, उनके जीवन में हमने ये साक्षात देखा था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया कि गोवा के लोग कितने ईमानदार होते हैं, कितने प्रतिभावान और मेहनती होते हैं, देश गोवा के चरित्र को मनोहर जी के भीतर देखता था। ■

‘आत्मनिर्भर भारत की कल्पना सहकारिता के सफल मॉडल के बगैर साकार नहीं हो सकती’

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 17 दिसंबर, 2021 को लखनऊ में सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया और देश के विकास के साथ देश के सभी लोगों के सम-विकास में सहकारिता की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सहकार भारती के अध्यक्ष श्री रमेश वैद्य, भारत सरकार में मंत्री श्री बी.एल. वर्मा, सहकार भारती के महामंत्री डॉ. उदय जोशी, उत्तर प्रदेश सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा, स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं सांसद श्री संतोष गंगवार, सहकार भारती, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमाशंकर और सहकार भारती, उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री प्रवीण सिंह जादौन सहित 27 राज्यों के 600 से अधिक जिलों से आये लगभग 3000 से अधिक सहकारी प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि वर्षों से सहकारी संगठनों, सहकारी समितियों, विशेषज्ञों और लाखों लोगों की यह मांग थी कि सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाना चाहिए जो सहकारिता के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे, उत्साह

दे और देश के विकास में योगदान दे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता के व्यापक उद्देश्य को समझते हुए जन-जन के विकास की अवधारणा के साथ सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि प्रधानमंत्रीजी ने मुझे देश का पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। मैं यह भी बखूबी समझता हूं कि यह कोई पद नहीं, बल्कि एक विशेष जिम्मेदारी है।

श्री शाह ने कहा कि देश के अर्थतंत्र को गति देने में आने वाले दिनों में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ की कल्पना भी सहकारिता के सफल मॉडल के बगैर साकार नहीं हो सकती। ■

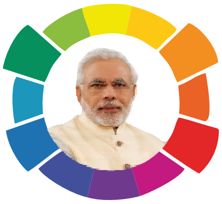

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

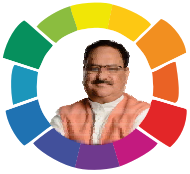

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)............................ (2)..............................

ईमेल : ....

सदस्यता					
एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.................................. दिनांक :............................ बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में महिला केंद्रित अनेक कार्यक्रमों के शुभारंभ अवसर पर जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक सामूहिक तस्वीर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 'जमाकर्ता पहले: गारंटी के साथ व तय समय-सीमा में बैंक जमा पर 5 लाख रुपये तक का बीमा भुगतान' विषय पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर जनरल बिपिन रावत और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह